सांध्य दैनिक

नई दृष्टिबिंदु

सच की शक्ति, जनता की दृष्टि

PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

"लोक सत्य के पक्ष में नहीं खड़े होते वो सिर्फये देखते हैं कि किस पक्ष के साथ संबंध बनाकर रखना अधिक लाभदायक है...!!"

अज्ञात...

वर्ष–01 अंक–158 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, शनिवार 27 जून 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए

नए प्रदेश अध्यक्ष की रेस तेज, सिंहदेव आगे, पटेल संतुलन साधेंगे, देवेन्द्र के नाम पर गंभीरता से विचार

9 जुलाई को दीपक बैज का कार्यकाल खत्म, 'मिशन 2028' के लिए हाईकमान के सामने विकल्पों की बिसात

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

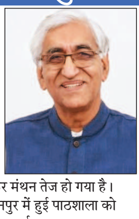

पीसीसी चीफ दीपक बैज का तीन साल का कार्यकाल 9 जुलाई को खत्म हो रहा है। मिशन 2028 की तैयारी के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नए अध्यक्ष को लेकर मंथन तेज हो गया है। राहुल गांधी की अभनपुर में हुई पाठशाला को संगठनात्मक सर्जरी का पूर्वाभ्यास माना जा रहा है। हाईकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती अनुभव और युवा जोश के बीच संतुलन साधने की है।

टीएस सिंहदेव सबसे मजबूत दावेदार

नए अध्यक्ष की दौड़ में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का नाम सबसे ऊपर है। 2023 की हार और गुटबाजी के बाद पार्टी को ऐसे चेहरे की तलाश है जिसकी बात हर गुट माने। सिंहदेव की बेदाग छवि, सरगुजा से मैदानी इलाकों तक स्वीकार्यता और खुद जिम्मेदारी लेने की इच्छा उन्हें मजबूत बनाती है। पार्टी का एक धड़ा मानता है कि भाजपा के संगठनात्मक तंत्र से लड़ने के लिए प्रशासनिक अनुभव वाले नेता की जरूरत है।

उमेश पटेल : सर्वस्वीकार्य चेहरा

सिंहदेव के बाद खरसिया विधायक और पूर्व मंत्री उमेश पटेल दूसरी पसंद हैं। उन्हें संगठन का बैलेंसिंग

फैक्टर माना जा रहा है। युवा होने के साथ उनके पास सरकार और संगठन दोनों का अनुभव है। वे भूपेश बघेल खेमे और राहुल गांधी–सचिन पायलट दोनों के करीबी हैं। हाईकमान यदि बुजुर्ग चेहरे से परहेज करे तो पटेल निर्विवाद विकल्प हो सकते हैं।

दीपक बैज भी रेस में, पर बदलाव की आहट

वर्तमान अध्यक्ष दीपक बैज ने आदिवासी समाज में पैठ बनाई है और वे खुद रेस में हैं। हालांकि बदलाव की बयार तेज है। राहुल गांधी की पाठशाला ने साफ कर दिया कि अब सिर्फ मैगी पॉलिटिक्स से काम नहीं चलेगा। अब

तय होना है कि पार्टी सिंहदेव के तजुर्बे पर भरोसा करेगी, उमेश पटेल से भविष्य का नेतृत्व गढ़ेगी या यादव का चुनाव करेगी। सचिन पायलट की रिपोर्ट और दिल्ली का फैसला तय करेगा कि कांटों का ताज किसके सिर सजेगा।

देवेंद्र यादव की मजबूत दावेदारी

भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की इस बार संगठन अध्यक्ष के लिए मजबूत दावेदारी है। प्रदेश में साहू समाज के बाद यादव समाज की बाहुल्यता है। यादव समाज को साधने और ओबीसी वर्ग को एकजुट करने देवेन्द्र कारगर साबित हो सकते हैं। भारत जोड़ों यात्रा के बाद देवेन्द्र यादव दिल्ली दरबार में नेताप्रतिपक्ष राहुल गांधी के बेहद चहेते हो गए हैं। राहुल गांधी ने उन्हें लोकसभा चुनाव के दरम्यान बिलासपुर लोकसभा से उम्मीदवार भी बनाया था। गांधी परिवार की निकटता के कारण देवेन्द्र यादव को कमान सौंपी जा सकती है। छात्र राजनीति के दौर में देवेन्द्र यादव भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पूरे प्रदेश में अपनी अलग फौज भी तैयारी की। अभी युवा कांग्रेस का चुनाव प्रदेश में चल रहा है जिसमें देवेन्द्र की टीम इस चुनाव में जुटी हुई है।

युवाओं में लोकप्रिय और आक्रामक छवि वाले यादव के नाम पर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को आपत्ति है। खासकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उनकी दूरियां युवक कांग्रेस चुनाव के शुरु होने से पहले बढ़ गई हैं। विरोधियों का तर्क है कि उनकी सक्रिय कार्यशैली से वरिष्ठ नेतृत्व किनारे हो सकता है और गुटबाजी बढ़ सकती है। संगठन का एक हिस्सा मानता है कि मिशन 2028 के लिए विवादों से दूर, सबको जोड़ने वाला चेहरा चाहिए।

जनप्रतिनिधियों के 20 से ज्यादा आपराधिक मामलों पर हाईकोर्ट की निगरानी हुई तेज

15 से अधिक मौजूदा–पूर्व MP-MLA के केस लंबित, समयबद्ध सुनवाई के निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / बिलासपुर

छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधियों से जुड़े लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई अब और तेज होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2026 की स्टेटस रिपोर्ट जारी कर प्रदेश की विशेष एमपी–एमएलए अदालतों में चल रहे मामलों की समीक्षा की है।

20 से ज्यादा केस विचाराधीन

रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 15 से अधिक वतर्मान और पूर्व सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ 20 से ज्यादा आपराधिक प्रकरण विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं। हाईकोर्ट ने सभी विशेष अदालतों को अनावश्यक देरी से बचते हुए सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। लंबित प्रकरणों की अद्यतन जानकारी भी मांगी गई है।

रायपुर–बिलासपुर से जांजगीर तक केस

रायपुर की विशेष एमपी–एमएलए अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक कवासी लखमा और देवेंद्र यादव के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई चल रही है। इनमें सरकारी कार्य में बाधा, प्रदर्शन और कानून–व्यवस्था से जुड़े मामले शामिल हैं। कवासी लखमा से जुड़े ईडी और शराब घोटाले के मामलों पर भी प्रक्रिया जारी है।

बिलासपुर की विशेष अदालत में मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन समेत अन्य मामलों की सुनवाई चल रही है। जांजगीर–चांपा में अकलतरा विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी के केस में न्यायिक प्रक्रिया जारी है। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के मामलों में भी सुनवाई हो रही है। कुछ मामलों में आरोप तय हो चुके हैं, तो कई में गवाहों के बयान और साक्ष्य दर्ज किए जा रहे हैं।

नियमित मॉनिटरिंग होगी

हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जनप्रतिनिधियों से जुड़े सभी लंबित आपराधिक मामलों की नियमित समीक्षा जारी रहेगी। इसका मकसद समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करना और न्यायिक प्रक्रिया में विलंब रोकना है।

बीएसपी में 250 टन स्क्रैप चोरी का पर्दाफाश अब वेट ब्रिज में चिप लगाकर 40 टन का खेल

रिमांड पर सुपरवाइजर ने खोले राज, क्राइम सीन री–क्रिएट

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भिलाई इस्पात संयंत्र में 250 टन लौह स्क्रैप चोरी का काला कारोबार अब सिस्टम के अंदर तक पहुंच गया है। रिमांड पर चल रहे हिमांशु ब्रदर्स के सुपरवाइजर निर्मल सिंह को लेकर पुलिस शुक्रवार को सीधे इरढ प्लांट पहुंची और रटर–3 व मैगडन क्षेत्र में क्राइम सीन री–क्रिएट कराया। निर्मल ने बताया कि रात में निगरानी ढीली होते ही चुंबकीय क्रेन से स्क्रैप लोड कर बाहर भेजा जाता था। उसके सुरागों से अब सिंडिकेट के बड़े नामों तक शिकंजा कसने की तैयारी है।

अब तक इस केस में ट्रांसपोर्टर संजय सिंह, सुपरवाइजर आकाश सिंह समेत 13 गिरफ्तार हो चुके हैं। 26 मई को अकलोरडीह के एके ट्रेडर्स से 250 टन फ्लू डस्ट समेत 3.22 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई थी। संजय सिंह की 3 करोड़ की अचल संपत्ति और 50 लाख के गहने भी राजसात किए जा चुके हैं।

कांटे में चिप, हर ट्रक पर 40 टन का फिक्स खेल

स्क्रैप कांड की परतें खुल ही रही थीं कि बोरिया गेट के वेट ब्रिज में बड़ा फ्रॉड सामने आ गया। सोमवार सुबह खाली कांटा ही 40 टन वजन दिखाने लगा। इंस्ट्रूमेंट टीम ने कंप्यूटर–केबल की जांच की तो बीच में एक संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी मिली। चिप हटाते ही कांटा सामान्य हो गया। आशंका है कि रिमोट से चुनिंदा ट्रकों का वजन 40 टन तक बढ़ाकर अतिरिक्त लौह सामग्री पार की जा रही थी।

ट्रांसपोटर्रों का आरोप है कि बिना अंदरूनी मदद के यह तकनीकी छेड़छाड़ मुमकिन नहीं। जुलाई 2025 में भी इसी कांटे की केबल में चिप जलने की बात सामने आई थी, पर कार्रवाई नहीं हुई।

सुरक्षा पर सवाल, FIR अब तक नहीं

लगातार दो बड़े खुलासों ने बीएसपी की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विजिलेंस जांच के बाद मामला CISF को सौंपा गया, लेकिन थाने में अब तक FIR दर्ज नहीं हुई। CISF का कहना है कि वेट ब्रिज पूरी तरह कंप्यूटरीकृत प्रणाली है और प्रबंधन का आंतरिक विषय है।

पुलिस का दावा है कि रटर–3 स्क्रैप यार्ड में रात की शिफ्ट में साई एसोसिएट की चुंबकीय क्रेन का फायदा उठाकर चोरी की जाती थी। अब निर्मल के बयानों से बीएसपी के कांटे से लेकर केबिन तक फैले नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। सवाल साफ है: 250 टन स्क्रैप और 40 टन का चिप–खेल आखिर किसके इशारे पर?

रावघाट में बिना अनुमति काटे 540 पेड़, अवैध सड़क पर वन विभाग का एक्शन

रावघाट में पहाड़ काटकर बनी सड़क से वन विभाग बेखबर, बिना अनुमति पेड़ों की कटाई

रेंजर–एसडीओ समेत 7 को नोटिस, 5 वनरक्षक–वनपाल हटाए गए, BSP को भी घेरा

नई दृष्टिबिंदु / कांकेर-भिलाई

रावघाट लौह अयस्क परियोजना के लिए बिना वन विभाग की अनुमति बनाई गई सड़क और सैकड़ों पेड़ों की अवैध कटाई का मामला गरमा गया है। वनमंडल भानुप्रतापपुर ने जांच के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए रेंजर, एसडीओ समेत 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पांच वनरक्षक और वनपाल को तत्काल प्रभाव से क्षेत्र से हटा दिया गया है। बीएसपी को भी नोटिस भेजा गया है।

1340 मीटर लंबी सड़क, पहाड़ काटकर बनाई

जांच में सामने आया कि रावघाट में लौह अयस्क परिवहन के लिए 1340 मीटर लंबी और 9.95 मीटर चौड़ी सड़क पहाड़ काटकर बनाई गई। इसके लिए बिना अनुमति करीब 540 पेड़ काटे गए। विभाग का कहना है कि यह संख्या बढ़ भी सकती है। पूर्व वनमंडलाधिकारी भानुप्रतापपुर ने पांच सदस्यीय टीम गठित कर मौके पर जांच कराई थी।

एसडीओ बोले– बीएसपी ने नहीं ली अनुमति

एसडीओ विजय चंद्रवंशी ने माना कि बीएसपी ने सड़क निर्माण के लिए वन विभाग से कोई अनुमति नहीं ली थी। वन विभाग को इसकी जानकारी तक नहीं थी। मामले में भारतीय वन अधिनियम 1927 का उल्लंघन हुआ है।

इन पर हुई कार्रवाई

वनमंडलाधिकारी प्रथम जैन के अनुसार एसडीओ विजय चंद्रवंशी और रेंजर वीरेंद्र यादव को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इसके अलावा निदयाल बेताल वनपाल परिक्षेत्र सहायक जैसगांव, आत्माराम पोटाई वनपाल परिक्षेत्र सहायक फूलपाड़, अश्विनी कुमार नेताम वनरक्षक दक्षिण मेसमाड़, सहादुर सिंह ठाकुर वनरक्षक फुलपाड़ और योगेश कुमार ठाकुर वनरक्षक अंजरेल पूर्व को क्षेत्र से हटाकर नोटिस जारी किया गया है।

बीएसपी को नोटिस, कार्रवाई तय : वनमंडलाधिकारी ने बताया कि अवैध सड़क निर्माण के मामले में बीएसपी को भी नोटिस जारी किया गया है। जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई है। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि इससे केंद्र और राज्य सरकार की छवि प्रभावित हुई है। अब निगाहें रावघाट परियोजना से जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई पर टिकी हैं।

2.25 करोड़ के गांजा तस्करी नेटवर्क का सरगना हुआ गिरफ्तार

व्हाट्सएप कॉल से कर रहा था रूट गाइड, तकनीकी साक्ष्यों से खुला राज, सिकंदराबाद से पकड़ा गया बलराम सैनी

नई दृष्टिबिंदु / महासमुंद

थाना बसना पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी सिंडिकेट के मुख्य सरगना बलराम सैनी उर्फ बल्लू को तेलंगाना के सिकंदराबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपी ओडिशा से हरियाणा तक 2.25 करोड़ रुपये के गांजा तस्करी नेटवर्क को चला रहा था। पुलिस ने व्हाट्सएप कॉल, सीडीआर और लोकेशन के विश्लेषण से मास्टरमाइंड तक पहुंच बनाई।

454 किलो गांजा पकड़ने से खुली थी कड़ी

30 मार्च 2026 को बसना पुलिस ने पलसापाली नाका पर नाकाबंदी कर बोलेरो पिकअप TS08UH8606 से 454.890 किलो गांजा जब्त किया था। इसकी कीमत करीब 2.27 करोड़ रुपये थी। मौके से वाहन चालक इमरान पिता लुकमान तेली, 36 वर्ष, निवासी पिलानी राजस्थान को गिरफ्तार किया गया था। खेप ओडिशा से लाई जा रही थी।

व्हाट्सएप से दे रहा था रूट की जानकारी गिरफ्तार आरोपी इमरान के बयान और

साइबर सेल से मिले तकनीकी साक्ष्यों से पता चला कि नेटवर्क का मुख्य संचालक बलराम सैनी है। घटना के दिन वह लगातार व्हाट्सएप कॉलिंग से इमरान को रूट गाइड कर रहा था। पुलिस ने आज उसे सिकंदराबाद से गिरफ्तार किया।

फूलबानी से चरखीदादरी तक फैला है नेटवर्क

पूछताछ में बलराम ने कबूला कि वह ओडिशा के फूलबानी निवासी विक्कू से गांजा मंगवाकर हरियाणा के चरखीदादरी और पिलानी में गोपाल व अन्य को बेचता था। आरोपी आदतन अपराधी है और 2019 में भी गांजा तस्करी में जेल जा चुका है।

2.35 करोड़ की संपत्ति जब्त

इस मामले में अब तक 454.890 किलो गांजा, बोलेरो पिकअप और तस्करी में प्रयुक्त 2 स्माटफीन जब्त किए गए हैं। कुल संपत्ति की कीमत करीब 2.35 करोड़ रुपये है। आरोपी को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट, सरायपाली के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार आरोपी में बलराम सैनी उर्फ बल्लू, 30 वर्ष, स्थायी पता इन्द्रगढ़ी कालोनी, गोहना, सोनीपत हरियाणा। वतर्मान पता ओल्ड बोवेनपल्ली क्रॉस रोड, सिकंदराबाद तेलंगाना। प्रकरणः थाना बसना अपराध क्रमांक 153/2026, धारा 20(इ)(उ), 29 एनडीपीएस एक्ट। महासमुंद पुलिस सोर्स से लेकर रिसीवर तक पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रही है।

कौशांबी में टोल प्लाजा से टकराया एलपीजी टैंकर, लगी भीषण आग, चालक जिंदा जला

कौशांबी। यूपी के कौशांबी में एक एलपीजी टैंकर बेकाबू होकर टोल प्लाजा से टकरा गया। टक्कर के बाद तेज धमाका हुआ और टैंकर में आग लग गई। हादसे में टैंकर चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। शव पूरी तरह जल गया और मौके से सिर्फ कंकाल का कुछ हिस्सा बरामद हुआ। धमाके और आग की चपेट में आकर पांच टोल कर्मचारी भी झुलस गए। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक टैंकर पूरी तरह जल चुका था। टोल प्लाजा के यार्ड में खड़ी 16 बाइकें और दो कारें भी आग की चपेट में आकर खाक हो गईं। आग बुझाने के बाद जब टीम ने टैंकर की जांच की तो अंदर से चालक की हड्डियां मिलीं। झुलसे टोलकर्मियों को अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण का अनूठा संगम, महिलाओं ने कचरे को बनाया आय का स्रोत

2730 किलो प्लास्टिक रिसायकल कर अर्जित किए 46,410 रुपए, दुर्ग मॉडल बना प्रदेश के लिए मिसाल

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण का अनूठा संगम दुर्ग जिले की ग्राम पंचायत कोलिहापुरी में देखने को मिला है। कलेक्टर अभिजीत सिंह एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग बजरंग कुमार दुबे के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत कोलिहापुरी ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में एक ऐसा मॉडल विकसित किया है, जो अब पूरे जिले के लिए प्रेरणास्रोत बन रहा है।

ग्राम पंचायत की महिला स्व-सहायता समूहों की दीदियों ने घर-घर से एकत्रित किए गए 2730 किलो प्लास्टिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से पृथक्करण कर उसे अधिकृत पुनर्चक्रण इकाई को विक्रय किया। इस पहल से समूह को कुल ?46,410 की आय प्राप्त हुई। यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि यदि कचरे का सही प्रबंधन किया जाए तो वह केवल अपशिष्ट नहीं, बल्कि आय का सशक्त माध्यम भी बन सकता है।

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सफल मॉडल

कोलिहापुरी में अपनाई गई कार्यप्रणाली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उत्कृष्ट उदाहरण है। ग्राम स्तर पर महिला स्व-सहायता समूह की सदस्याएं प्रतिदिन घर-घर जाकर गीला, सूखा एवं प्लास्टिक कचरे का पृथक संग्रहण करती हैं तथा ग्रामीणों को स्रोत पर ही कचरा अलग-अलग रखने के लिए जागरूक करती हैं।

विकासखंड स्तर पर संग्रहित प्लास्टिक को विकासखंड दुर्ग स्थित एमआरएफ-पीडब्ल्यूएमयू सेंटर में पहुंचाया जाता है, जहां उसे गुणवत्ता एवं प्रकार के आधार पर PET, HDPE, LDPE सहित विभिन्न श्रेणियों में अलग किया जाता है। इससे प्लास्टिक का बाजार मूल्य बढ़ जाता है।

विक्रय स्तर पर पृथक किए गए प्लास्टिक को अधिकृत रिसायकल इकाइयों को बेचा जाता है और प्राप्त राशि सीधे महिला समूहों के खातों में जमा की जाती है, जिससे उनकी आय और आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि हो रही है।

अन्य ग्राम पंचायतों में भी विस्तार

कोलिहापुरी की सफलता से प्रेरित होकर विकासखंड धमधा की ग्राम पंचायत लिटिया तथा विकासखंड पाटन की ग्राम पंचायत पतोरा और गाड़ाडीह में भी इसी मॉडल पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य संचालित किया जा रहा है। जिला प्रशासन का लक्ष्य आगामी समय में जिले की सभी ग्राम पंचायतों में इस मॉडल को लागू करना है।

इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग बजरंग कुमार दुबे ने कहा, "कोलिहापुरी की महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि स्वच्छता और आजीविका एक-दूसरे के पूरक हैं। सही मार्गदर्शन और सामुदायिक सहभागिता से कचरे को भी आर्थिक संसाधन में बदला जा सकता है। जिला प्रशासन ऐसे नवाचारों को निरंतर प्रोत्साहित करता रहेगा।"

कोलिहापुरी की यह पहल न केवल स्वच्छता अभियान को नई दिशा दे रही है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है।

स्वच्छ भारत मिशन और आजीविका संवर्धन की दोहरी सफलता

यह पहल स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के उद्देश्यों को साकार करने के साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका के अवसर भी निर्मित कर रही है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुरूप ग्रामीणों को गीला, सूखा, घरेलू खतरनाक एवं प्लास्टिक कचरे को अलग-अलग रखने के लिए निरंतर जागरूक किया जा रहा है। प्लास्टिक कचरे की गुणवत्ता के अनुसार पृथक्करण से मिलने वाले बेहतर मूल्य की जानकारी के बाद महिलाओं ने कचरे को अब "संपदा" के रूप में देखना शुरू कर दिया है।

खास खबर

भिलाई के आवासविहीन 55 परिवारों को मिला आवास, लॉटरी पद्धति से हुआ आबंटन

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा मकानहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए गुरुवार को निगम सभागार में लॉटरी पद्धति के माध्यम से 55 हितग्राहियों को आवास आबंटित किए गए। सभी आवास मोर मकान-मोर आस एवं मोर मकान-मोर चिन्हारी घटक से निर्मित है। आवास आबंटन कार्यक्रम में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय, नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा एवं पार्षद हरिओम तिवारी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

निगम सभागार में लॉटरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई, जिसमें विभिन्न आवासीय परियोजनाओं के तहत कुल 55 मकानहीन परिवारों को आवास आबंटित किए गए। इनमें ग्रीन वैली खम्हरिया में 20, माइल स्टोन स्कूल के पीछे स्थित आवासों में 17, रजत बिल्डर्स शांति नगर में 3, आम्रपाली हाउसिंग बोर्ड फेस-01 में 2 तथा सूर्य विहार के पीछे स्थित आवासीय परिसर में 13 हितग्राहियों को आवास प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान हितग्राहियों में उत्साह का माहौल रहा। निगम प्रशासन ने बताया कि आवास आबंटन की प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से की गई है, जिससे पात्र परिवारों को स्थायी आवास की सुविधा मिल सके। इस अवसर पर आवास प्रभारी विद्याधर देवांगन, सीएलटीसी किरण चतुर्वेदी, आवास विभाग की नम्रता ठाकुर, जागेश्वर साहू, थलेश्वर जोशी, जी मोहन राव एवं नूतन साहू सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

नंदिनी नगर पुलिस ने 6 घंटे में सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी, दो गिरफ्तार

भिलाई। ग्राम डूमर स्थित पानी टंकी के पास मिले अज्ञात युवक के शव की पहचान कर नंदिनी नगर पुलिस ने मात्र 6 घंटे में अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शराब पीने के दौरान हुए विवाद में मुख्य आरोपी ने सब्बल से सिर पर वार कर हत्या की थी। गुरुवार को ग्राम डूमर के कोटवार ने सूचना दी कि पानी टंकी के पास सिंटेक्स रखने वाले चबूतरे पर एक युवक का शव पड़ा है। सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। पुलिस मौके पर पहुंची तो मृतक की पहचान नहीं हो सकी। गोदना और अन्य साक्ष्यों के आधार पर शिनाख्त चेतन ठाकुर, 18 वर्ष, निवासी ग्राम पथरिया के रूप में हुई।

जांच में सामने आया कि मृतक चेतन ठाकुर, सोमनाथ उर्फ लालू यादव और राहुल कुर्रे रात में साथ शराब पी रहे थे। इसी दौरान विवाद होने पर रात करीब 1 बजे मुख्य आरोपी सोमनाथ उर्फ लालू यादव ने सब्बल से चेतन के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने सब्बल और अपने कपड़े पास के तालाब में फेंक दिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। मुख्य आरोपी की निशानदेही पर एसडीआरएफ टीम की मदद से तालाब से हत्या में प्रयुक्त सब्बल और आरोपी के कपड़े बरामद किए गए। पुलिस ने सोमनाथ उर्फ लालू यादव, 22 वर्ष, और राहुल कुर्रे, 22 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम डूमर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। हत्या का मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्राम डूमर, पानी टंकी के पास स्थित सिंटेक्स का चबूतरा, थाना नंदिनी नगर, जिला दुर्ग। पुलिस ने एक सब्बल और आरोपी के कपड़े जब्त किए। थाना प्रभारी व स्टाफ की त्वरित कार्रवाई और एसडीआरएफ टीम की भूमिका सराहनीय रही।

अनोखा अभियान : टैक्स जमा करने वाले करदाताओं का पौधा भेंट कर किया सम्मान

करदाता सम्मान के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश, हरियाली बढ़ाने की अनूठी पहल

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

नगर पालिक निगम दुर्ग ने करदाताओं के सम्मान और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ जोड़ते हुए एक अभिनव पहल की शुरुआत की। निगम प्रशासन ने टैक्स काउंटरों में संपत्तिकर एवं अन्य कर जमा करने पहुंचे जागरूक करदाताओं का पौधा भेंट कर स्वागत एवं सम्मान किया। निगम की इस पहल को नागरिकों ने सराहनीय बताते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक प्रयास माना।

निगम परिसर स्थित टैक्स काउंटरों में बड़ी संख्या में नागरिक कर जमा करने पहुंचे। इस दौरान निगम अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रत्येक करदाता को पौधा भेंट कर समय पर कर भुगतान करने की उनकी जिम्मेदारी और जागरूकता की सराहना की।

निगम प्रशासन ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य केवल राजस्व संग्रह करना नहीं, बल्कि नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित करना भी है। पौधरोपण के माध्यम से शहर को अधिक हराभरा, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने का संदेश दिया गया। प्रशासन ने कहा कि नगर विकास में करदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नागरिकों द्वारा समय पर कर जमा करने से सड़क, नाली, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता सहित विभिन्न जनहित एवं विकास कार्यों को गति मिलती है।

निगम प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की कि वे समय पर अपना कर जमा करें और वर्षा ऋतु का लाभ उठाते हुए कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं तथा उसकी नियमित देखभाल भी करें। प्रशासन का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की बड़ी आवश्यकता है। यदि प्रत्येक नागरिक एक पौधा लगाकर उसे वृक्ष बनने तक संरक्षित करे, तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और हरित वातावरण मिल सकेगा। नगर

निगम ने भविष्य में भी जनभागीदारी आधारित ऐसे नवाचार जारी रखने की बात कही है, जिससे शहर के विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिले।

निगम में संपत्ति कर में 6% छूट पाने का अंतिम मौका

नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा शहर के समस्त करदाता वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्तिकर (प्रॉपर्टी टैक्स) का भुगतान 30 जून 2026 तक करने वाले करदाताओं को नियमानुसार 6 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। निगम प्रशासन ने नागरिकों से इस सुविधा का लाभ उठाते हुए निर्धारित तिथि के पूर्व अपना कर जमा करने की अपील की है।

नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि समय पर कर भुगतान से न केवल करदाताओं को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, बल्कि शहर में चल रहे विकास एवं जनसुविधा कार्यों के लिए आवश्यक राजस्व भी उपलब्ध होगा। निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कर भुगतान की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया गया है, ताकि करदाता बिना किसी परेशानी के अपना कर जमा कर सकें। नागरिक नगर निगम कार्यालय में उपस्थित होकर नकद के माध्यम से कर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस सहित विभिन्न डिजिटल माध्यमों से भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। करदाता घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी अपना संपत्तिकर जमा कर सकते हैं। नगर निगम दुर्ग ने सभी करदाताओं से आग्रह किया है कि वे अंतिम दिनों की भीड़ से बचने के लिए 30 जून 2026 से पूर्व अपना संपत्तिकर जमा करें तथा 6 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त करें। निगम प्रशासन ने कहा है कि समय पर कर भुगतान शहर के विकास में नागरिकों की महत्वपूर्ण भागीदारी को भी दर्शाता है।

भू-माफियाओं और कब्जाधारियों पर प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय भूमि की सुरक्षा और भू-माफियाओं के विरुद्ध अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दुर्ग जिले में जिला प्रशासन लगातार कड़ी कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशन में प्रशासन ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के लिए जिले में कोई स्थान नहीं है और ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोर एवं विधिसम्मत कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

इसी क्रम में धमधा तहसील के ग्राम बसनी में लंबे समय से शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाकर शासन की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा शासकीय भूमि पर झटका तार लगाकर तथा खरीफ एवं रबी फसलों की खेती कर अवैध कब्जा किया गया था। शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर अभिजीत सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए।

तहसीलदार धमधा द्वारा हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर राजस्व प्रकरण में विस्तृत जांच और सुनवाई की गई। तथ्यों की पुष्टि होने पर संबंधित कब्जाधारियों के विरुद्ध विधिवत बेदखली आदेश पारित किया गया। आदेश के पालन में 22 जून 2026 को राजस्व विभाग और ग्राम पंचायत बसनी के संयुक्त प्रयास से व्यापक कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया।

तहसीलदार मीना साहू ने बताया कि कार्रवाई के दौरान सेवाराम लोधी द्वारा शासकीय खसरा नंबर 1077 की 20 डिसमिल तथा खसरा नंबर 1188 की 0.34 हेक्टेयर भूमि पर किए गए कब्जे को हटाया गया। इसी प्रकार राजकुमार लोधी के कब्जे से 7 डिसमिल तथा राजकपूर लोधी के कब्जे से 13 डिसमिल शासकीय भूमि मुक्त कराई गई। वहीं शिवकुमार मौर्य द्वारा खसरा नंबर 1077 की 8 डिसमिल भूमि तथा खसरा नंबर 1076 की 0.19 हेक्टेयर भूमि पर किए गए अवैध कब्जे और लगाए गए झटका तार को भी हटाकर भूमि को शासन के पक्ष में सुरक्षित किया गया। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण और विधिसम्मत ढंग से संपन्न हुई, जिसमें राजस्व निरीक्षक धमधा, राजस्व निरीक्षक पेण्ड्रावन, हल्का पटवारी एवं ग्राम पंचायत सचिव उपस्थित रहे।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। भू-माफियाओं, अवैध कब्जाधारियों और शासकीय भूमि का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन की इस निर्णायक पहल से ग्रामीणों में संतोष और विश्वास का माहौल है तथा शासकीय भूमि को संरक्षित करने के इस कदम की व्यापक सराहना की जा रही है।

भारतीय नाविकों की हत्या के विरोध में स्वदेशी जागरण मंच ने निकाली आक्रोश रैली

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई-दुर्ग

ओमान में तीन भारतीय नाविकों की हत्या की घटना के विरोध में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा दुर्ग में आक्रोश मार्च रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भारत माता के जयघोष के साथ कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करते हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर सक्षम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

इस अवसर पर जिला संयोजक गुरुप्रसाद तिवारी ने कहा कि विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों एवं नाविकों की सुरक्षा को लेकर देशभर में चिंता बढ़ी है। ओमान में तीन भारतीय नाविकों की निर्मम हत्या ने पूरे देश को आहत किया है। उन्होंने दोषियों के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की मांग की।

प्रांत सह संयोजक दिनेश पाटिल ने कहा कि इस घटना ने विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने आवश्यक हैं।

ज्ञापन के माध्यम से स्वदेशी जागरण मंच ने प्रमुख मांगें रखीं हैं जिनमें विदेशों में कार्यरत भारतीय नाविकों एवं नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तीनों भारतीय नाविकों की हत्या के दोषियों को कठोरतम दंड दिया जाए। विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रभावी एवं सुदृढ़ राष्ट्रीय नीति बनाई जाए। भारतीय नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा एवं अधिकारों से जुड़े मामलों में भारत सरकार दृढ़ एवं प्रभावी कदम उठाए।

मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि यह केवल तीन भारतीय नागरिकों की हत्या का मामला नहीं है, बल्कि विश्वभर में कार्यरत लाखों भारतीयों की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा विषय है। ऐसे मामलों में राष्ट्र की संवेदनशीलता और दृढ़ता दोनों का प्रदर्शन आवश्यक है। कार्यक्रम में संरक्षक गणेश शंकर देशपांडे, अजय तिवारी, दिनेश पाटिल, दिव्या कलिहारी, संजय चौबे, भोजराज सिन्हा, पोषण साहू, बॉबी दास, मोहन बागुल, दिव्या भसीन, सरोजनी पाणिग्राही, गीतांजलि कौशिक सहित सामाजिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

आईसीएआई भिलाई ब्रांच ने किया आरबीआई नागपुर का शैक्षणिक भ्रमण

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

आईसीएआई भिलाई द्वारा मंगलवार को 42 चार्टर्ड अकाउंटेंसी विद्यार्थियों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सफल और ज्ञानवर्धक शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया गया। इस भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को आरबीआई की कार्यप्रणाली, मौद्रिक नीति, मुद्रा प्रबंधन तथा देश की अर्थव्यवस्था में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई। यह अनुभव विद्यार्थियों के लिए कक्षा में पढ़े गए विषयों को वास्तविक रूप में समझने का एक उत्कृष्ट अवसर रहा। विद्यार्थियों ने आरबीआई भवन की भव्य वास्तुकला और दीवारों पर की गई सुंदर कलाकृतियों की भी सराहना की, जिसने सभी को विशेष रूप से आकर्षित किया।

इस अवसर पर रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सभी प्रतिभागियों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई, जिसकी विद्यार्थियों ने हृदय से प्रशंसा की। ब्रांच ने इस सफल आयोजन में सहयोग, समन्वय एवं आतिथ्य के लिए आरबीआई के डायरेक्टर व असिस्टेंट डायरेक्टर तथा अन्य अधिकारियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया। सीए विद्यार्थियों ने चैयरमैन सीए सुखदेव राठी, सचिव सीए प्रतीक अग्रवाल, तलविंदर सिंह, CICASA Chairman तथा CICASA Managing Committee के विशेष योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इन्हीं सभी के संयुक्त प्रयासों से यह भ्रमण अत्यंत सफल और यादगार बन सका। इसके अतिरिक्त, यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दादा ब्रदर्स का विशेष धन्यवाद व्यक्त किया गया।

पेंशन से वंचित हितग्राही, अरुण वोरा से लगाई मदद की गुहार

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

शहर में पूर्व विधायक अरुण वोरा के दौरे के दौरान सोमवार को अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर कुछ पीड़ित नागरिकों ने अरुण वोरा की गाड़ी को सड़क पर रोक लिया। लोगों ने उन्हें अपनी परेशानियों से अवगत कराते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

इस दौरान एक दिव्यांग हितग्राही ने भावुक होकर बताया कि उन्हें निराश्रित पेंशन योजना की राशि कई महीनों से प्राप्त नहीं हुई है। पेंशन बंद होने के कारण उनके सामने रोजमर्रा के खर्चों और जीवन-यापन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

पीड़ितों ने बताया कि दुर्ग में 3000 से अधिक जरूरतमंद हितग्राही निराश्रित पेंशन की राशि से वंचित हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि समस्या के समाधान के लिए वे कई बार आवेदन दे चुके हैं तथा विभागीय अधिकारियों और कलेक्टर कार्यालय के लगातार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। नागरिकों की पीड़ा सुनने के बाद

पूर्व विधायक अरुण वोरा ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने मौके पर ही नगर निगम आयुक्त से चर्चा कर पूरी स्थिति से अवगत कराया और प्रभावित हितग्राहियों की समस्या का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया।

इस अवसर पर अरुण वोरा ने कहा कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। जरूरतमंद, वृद्ध और दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों से वंचित रखना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के लिए ये योजनाएं जीवन का सहारा हैं, उन्हें महीनों तक राशि के लिए भटकना पड़े, यह प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। वोरा ने आश्वस्त किया कि प्रभावित हितग्राहियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे और संबंधित अधिकारियों के समक्ष इस विषय को प्रमुखता से उठाया जाएगा, ताकि पात्र लोगों को जल्द से जल्द उनका अधिकार मिल सके।

आवास निर्माण तक सीमित रहा मंडल अब अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में भी प्रदेश के विकास को देगा नई गति

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल के नए लोगो का किया विमोचन

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नया रायपुर स्थित सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के नवीन लोगो का विमोचन किया। इस अवसर पर वर्ष 2025 के आवास मेले में आवास बुक करने वाले हितग्राहियों को लकी ड्रा के माध्यम से कार, स्कूटी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी सहित विभिन्न पुरस्कार वितरित किए गए। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का नया लोगो तैयार करने वाले श्री अंशुल कश्यप को शुभकामनाएं दी और प्रतियोगिता की पुरस्कार राशि ढाई लाख रुपए का चेक सौंपा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक परिवार का अपना पक्का घर होने का सपना होता है और राज्य सरकार इस सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पूर्व में केवल गृह निर्माण तक सीमित रहा मंडल अब अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में मंडल ने उल्लेखनीय प्रगति की है और आर्थिक चुनौतियों से उबरते हुए मंडल ने लगभग 7,388 संपत्तियों का विक्रय कर 1,532 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंडल के अध्यक्ष तथा पूरी टीम को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने सभी संकल्पों और वायदों को तेजी से पूरा किया है। सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद साढ़े दस लाख से अधिक परिवार के आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा प्रतिदिन लगभग 1,600 नए आवास तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुर्नवास के लिए केंद्र सरकार से 15 हजार अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए गए हैं तथा विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए भी विशेष आवास योजना संचालित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन हमारे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 'सेवा सेतु' के माध्यम से 450 से अधिक शासकीय सेवाएं अब मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 भी प्रारंभ की गई है, जहां नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज कर समयबद्ध समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में लगभग 65 हजार घरों में रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के माध्यम से सरकार घर में सोलर संयंत्र लगाने के लिए आकर्षक सब्सिडी भी दे रही है और इन परिवारों लिए आने वाले समय में बिजली पूरी तरह मुफ्त हो जाएगी और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेच पाएंगें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के माध्यम से लंबित बिजली बिल के भुगतान का भी बड़ा अवसर दिया है और बिल पर लगने वाले सरचार्ज समेत आकर्षक छूट का प्रावधान किया है। श्री साय ने कहा कि सरकार न केवल जनहितैषी योजनाएं लागू कर रही है बल्कि सुशासन तिहार के माध्यम से उसका फीडबैक लेने लोगों के बीच भी गई। दो महीने लगातार जनता से फीडबैक लेकर व्यवस्थाओं में सुधार का काम किया गया है। उन्होंने इस दौरान शासन की विभिन्न नवाचारी पहल की जानकारी देते हुए सुशासन और पारदर्शी सरकार के संकल्प को दोहराया।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में विभाग में व्यापक प्रशासनिक सुधार लागू किए गए हैं। गृह निर्माण मंडल को अधोसंरचना विकास मंडल के रूप में नई पहचान देकर प्रदेश के पूंजीगत व्यय और विकास कार्यों में इसकी भूमिका का विस्तार किया गया है। मंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय करने वाले विभागों को वित्तीय और मानव संसाधन के माध्यम से सक्षम बनाने का काम किया है ताकि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि अब किसी भी नई आवासीय परियोजना का निर्माण तभी प्रारंभ होगा जब पर्याप्त बुकिंग सुनिश्चित हो जाएगी, जिससे अनावश्यक निर्माण और वित्तीय जोखिम से बचा जा सके। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू कर वर्षों से लंबित संपत्तियों के विक्रय को गति दी तथा वित्तीय अनुशासन स्थापित किया। इसके परिणामस्वरूप मंडल की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और अब यह अधोसंरचना विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए तैयार है।

मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में मंडल ने नई कार्य संस्कृति अपनाई है। गृह निर्माण मंडल का विस्तार कर अधोसंरचना विकास मंडल बनाया जाना प्रदेश के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में मंडल ने रिकॉर्ड संपत्तियों का विक्रय कर नई उपलब्धियां हासिल की हैं और भविष्य में मांग आधारित, गुणवत्तापूर्ण तथा वित्तीय रूप से व्यवहारिक परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा।

कार्यक्रम में लकी ड्रा के नौ विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। सारंगढ़ की श्रीमती पूजा बरेठ को प्रथम पुरस्कार के रूप में कार प्रदान की गई। इसके अलावा स्कूटी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी सहित अन्य आकर्षक पुरस्कार भी वितरित किए गए। इस अवसर पर आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ,आयुक्त अवनीश शरण, तथा विभाग एवं मंडल के वरिष्ठ अधिकारी और हितग्राही उपस्थित थे।

खास खबर

रबर टायर के बिना आयरन केजव्हील ट्रैक्टरों के सड़क पर संचालन पर सख्ती

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मोटर वाहन नियमों के उल्लंघन पर होगी चालानी कार्रवाई, परिवहन विभाग ने जारी किए निर्देश

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सशक्त नेतृत्व और परिवहन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सड़क सुरक्षा और मोटर वाहन नियमों के प्रभावी पालन के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में परिवहन विभाग ने रबर टायर के बिना दोहरे लोहे के पिंजरे (आयरन केजव्हील) वाले ट्रैक्टरों के सामान्य सड़कों पर संचालन पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई : परिवहन विभाग ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे ट्रैक्टरों के सड़क पर संचालन पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

खेतों के लिए बने हैं आयरन केजव्हील : परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ट्रैक्टरों में लगाए जाने वाले आयरन केजव्हील केवल कृषि कार्य और खेतों में उपयोग के लिए बनाए गए हैं। इन्हें रबर टायर के स्थान पर डामर, सीमेंट की सड़कों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलाना मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।

सड़कें हो रही हैं क्षतिग्रस्त, दुर्घटना का भी खतर : लोक निर्माण विभाग के अनुसार ऐसे ट्रैक्टरों के सड़क पर चलने से डामर और सीमेंट की सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। साथ ही दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने इस पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगा जनजागरुकता अभियान : जिला प्रशासन के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके माध्यम से किसानों और वाहन चालकों को मोटर वाहन नियमों तथा आयरन केजव्हील के सुरक्षित एवं निर्धारित उपयोग की जानकारी दी जाएगी।

मीडिया के माध्यम से होगा व्यापक प्रचार-प्रसार : परिवहन विभाग ने स्थानीय समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विशेष अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा मोटर वाहन नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना है।

छात्रावासों में लापरवाही पर प्रशासन हुआ सख्त, भृत्य और छात्रावास अधीक्षक हुए निलंबित

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के संकल्प के अनुरूप सुकमा जिले में छात्रावासों एवं आश्रमों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 प्रारंभ होने से पहले कलेक्टर के नेतृत्व में छात्रावासों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें लापरवाही और अव्यवस्था पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। 25 जून को कलेक्टर एवं सहायक आयुक्त द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में कई छात्रावासों एवं आश्रमों में साफ-सफाई की कमी, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अनुपस्थिति तथा संचालन में लापरवाही जैसी गंभीर कमियां पाई गईं। पूर्व में समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के बावजूद सुधार नहीं होने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि छात्रावासों और आश्रमों में अध्ययनरत बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और सुविधाओं के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन की मंशा के अनुरूप सभी संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

नक्सलमुक्त बस्तर के चहुंमुखी विकास के लिए विजय शर्मा ने समाज प्रमुखों से मांगा सहयोग

सर्व आदिवासी समाज प्रमुखों की बैठक में सामाजिक सशक्तिकरण, पेसा क्रियान्वयन और देवस्थलों के संरक्षण पर हुई व्यापक चर्चा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा जिला पंचायत कांकेर सभाकक्ष में सर्व आदिवासी समाज प्रमुखों की बैठक लेकर बस्तर के नक्सल उन्मूलन के बाद चहुंमुखी विकास, सामाजिक एकता तथा आदिवासियों की पारंपरिक संस्कृति और विरासत को सहेजने, संरक्षित करने पर चर्चा की। जिसमें जिले में पेसा एक्ट का समुचित क्रियान्वयन और पारंपरिक देव स्थलों को संरक्षित करने जैसे विषयों पर द्विपक्षीय सकारात्मक चर्चा हुई। इस दौरान समाज प्रमुखों ने भी बारी बारी से सुझाव दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में समाज प्रमुखों से कहा कि किसी समाज की परंपरा और सांस्कृतिक धरोहरों व पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किसी बड़े लक्ष्य की सफलता समाज के सहयोग से ही संभव होती है और बस्तर में नक्सल उन्मूलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।

उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र की मुख्यधारा से टूट कर हिंसा का मार्ग अपनाने वाले युवाओं को वापस मुख्यधारा में लेकर आने में समाज प्रमुखों ने सराहनीय कार्य किया, जिसमें सुरक्षा बलों और जवानों का सतत सहयोग मिला, जिसके फलस्वरूप आज बस्तर का लाल आतंक से मुक्त होना संभव हुआ। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि आज वर्षों से बंद मेला-मड़ई, बाजार, हाट अब आबाद होने लगे हैं। पहले जहां रिश्तेदार भी घर आने में डरते थे वे भी बेखौफ आने जाने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी वे पहली बार (नक्सलवाद से) आजाद होने का अनुभव कर रहे हैं।

सुविधा केंद्र के रूप में विकसित हो रहे अब सुरक्षा कैम्प

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि कतिपय बाहरी लोग स्थानीय लोगों में भ्रम फैला रहे हैं कि बस्तर के संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। इस पर उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट किया है कि बस्तर का विकास बस्तर के युवाओं और लोगों के द्वारा ही किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय संसाधनों का प्रयोग कर ही ग्रामों का विकास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए शुरुआत के रूप में सुरक्षा कैम्पों को सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा स्थानीय संसाधनों से ही विकसित किया जाएगा।

197 गांवों के देव स्थलों का राजस्व रिकॉर्ड

समाज प्रमुखों से चर्चा के दौरान श्री शर्मा ने बताया कि इसी क्रम में अब बस्तर के देव स्थलों को संरक्षित करने के लिए 197 गांवों के देव स्थलों का राजस्व रिकॉर्ड में चिन्हांकन कर उसे स्थायी पंजीयन की व्यवस्था की जा रही है ताकि देव स्थलों को अच्छे से संरक्षित किया जा सके। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा पेसा एक्ट को और भी सशक्त करने का कार्य किया गया है। इसके लिए पहली बार सरकार ने गांव गांव में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर पेसा मोबिलाइजर, कोऑर्डिनेटर रखने का कार्य किया जा रहा है।

जेल से भी पुनर्वास की व्यवस्था

समाज प्रमुखों की जेल में बंद भटके हुए युवाओं के पुनर्वास पर चिंता के संबंध में उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि हमने हर युवा को मुख्यधारा में लाने के लिए जेल से भी पुनर्वास की व्यवस्था की है। इसके लिए समाज को भी प्रेरित करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि अब पुनर्वासित युवा खुद भी जेल में जाकर भटके युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अन्य मतों में जाने वाले लोगों के साथ सामाजिक स्तर पर चर्चा कर शांति स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा शासन द्वारा भोले भाले ग्रामीणों की रक्षा के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक का निर्माण भी किया गया है।

इस अवसर पर सांसद भोजराज नाग ने कहा कि समाज में वैचारिक चिंतन की आवश्यकता है, ग्रामों की संस्कृति के संरक्षण की जरूरत है। उन्होंने विकास के साथ स्थानीय लोगों का भी विकास के लिए कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कहा कि विकास के लिए समाज के प्रतिनिधि और प्रशासन के समन्वय के द्वारा आगे बढ़ना है। सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव रखे। उन्होंने सभी सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए समाज की सहभागिता से बस्तर के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य करने का विश्वास दिलाया।

इस अवसर राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत, अंतागढ़ विधायक विक्रम उसेंडी, कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर सहित गोंडवाना समाज के अध्यक्ष सुमेर सिंह नाग, सर्व आदिवासी समाज के जिला सचिव राजेश भास्कर सहित विभिन्न आदिवासी समाज के प्रमुखगण मौजूद थे।

मुख्यमंत्री साय की पहल से जशपुर की महिलाएं बनेंगी 'ड्रोन दीदी'

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-जशपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और कृषि में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में जशपुर जिले की स्व-सहायता समूहों की महिलाएं नई पहचान बना रही हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत जिले की चयनित महिलाएं इन दिनों रायपुर स्थित आईटीएम विश्वविद्यालय में ड्रोन संचालन एवं रिमोट पायलटिंग का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।

यह प्रशिक्षण महिलाओं को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने के साथ उन्हें कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाएं ड्रोन आधारित कृषि सेवाएं देने के लिए दक्ष बन रही हैं। प्रशिक्षण के दौरान ड्रोन दीदियों को ड्रोन की तकनीकी संरचना, सुरक्षित उड़ान संचालन, रिमोट पायलटिंग, फसलों में उर्वरक एवं कीटनाशकों का वैज्ञानिक छिड़काव, ड्रोन के रखरखाव तथा कृषि क्षेत्र में उसके व्यावहारिक उपयोग की विस्तृत जानकारी दी जा रही है।

प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद ये ड्रोन दीदियां जशपुर जिले के किसानों को ड्रोन के माध्यम से नैनो उर्वरक, कीटनाशक एवं अन्य कृषि कार्यों की सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। इससे कृषि कार्य कम समय में, कम लागत पर और अधिक प्रभावी ढंग से किए जा सकेंगे। साथ ही वैज्ञानिक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में जशपुर प्रवास के दौरान प्रशिक्षण के लिए रवाना हो रही ड्रोन दीदियों की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इससे पूर्व 17 अप्रैल 2026 को रणजीता स्टेडियम में आयोजित 'लखपति दीदी' कार्यक्रम के दौरान ड्रोन दीदी एवं उन्नत सॉयल टेस्टिंग मशीन भी प्रदान की गई थी।

उप संचालक कृषि, जशपुर के अनुसार प्रशिक्षण के बाद ड्रोन दीदियां जिले के विभिन्न विकासखंडों में किसानों को तकनीक आधारित कृषि सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। इससे खेती में समय की बचत, लागत में कमी और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप महिलाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग का विश्वास है कि यह पहल जशपुर में तकनीक आधारित कृषि को नई गति देने के साथ महिला स्व-सहायता समूहों की आर्थिक सशक्तता और किसानों की आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बोड़ागांव में ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाकर किया संवाद

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-बस्तर-कांकेर

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने उत्तर बस्तर कांकेर प्रवास के दौरान अंतागढ़ विकासखंड के ग्राम बोड़ागांव स्थित सीएएफ कैंप परिसर में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद करते हुए शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी ढाई महीने के भीतर प्रत्येक ग्रामीण का बैंक खाते की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंच सके।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने चौपाल में ग्रामीणों से चर्चा के दौरान क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने, दुग्ध उत्पादन को आजीविका के साधन के रूप में विकसित करने तथा लघु वनोपज के प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने आधुनिक ढंग से दुग्ध उत्पादन के लिए इसमें रुचि लेने वाले 10-10 ग्रामीणों की टीम गठित कर गुजरात में एक्पोजर विजिट कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग से ग्रामीणों को रोजगार और आय के नए अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। उन्होंने महिला स्व सहायता समूहों से अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ने तथा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक पहल करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने से आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी।

आमाबेड़ा में किसान सदन निर्माण के लिए 15 लाख रुपये की स्वीकृति

इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने बोड़ागांव में स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए अटल डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित करने एवं आमाबेड़ा में किसान सदन निर्माण के लिए 15 लाख रुपये की स्वीकृति देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि डिजिटल सेवाओं और किसानों के लिए आवश्यक सुविधाओं के विस्तार से ग्रामीणों को बेहतर लाभ मिलेगा।

ग्रामीणों ने उप मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी आवश्यकताओं और स्थानीय समस्याओं से भी अवगत कराया, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर कांकेर सांसद भोजराज नाग और अंतागढ़ विधायक विक्रम उसेंडी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए नक्सलवाद की समाप्ति के बाद ग्रामीणों को शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं से जुड़कर विकास की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत, जिले के कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, एएसपी आकाश श्रीश्रीमाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

संपादकीय

सूखे की आहट : मुकाबले को युद्ध स्तर पर हो तैयारी

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के कमजोर रहने की चिंताओं के बीच देश के कृषि क्षेत्र के सामने सूखे की चुनौती पैदा होने की आशंका बलवती हुई है। हाल-फिलहाल बारिश में चालीस से छियालीस प्रतिशत की कमी मापी गई है। देश के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दो जुलाई तक मानसून की सक्रियता कम रहने के अनुमान के कारण खरीफ की फसल को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार ने कम बारिश वाले 315 जिलों में से 111 ऐसे जिलों की पहचान की है, जो सूखे की दृष्टि से ज्यादा जोखिम वाले हो सकते हैं। जो आसन्न संकट की गंभीरता को भी दर्शाता है।

यह विडंबना है कि तमाम सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के बावजूद आज देश में खेती की मॉनसून की बारिश पर निर्भरता बनी हुई है। यही वजह है कि मॉनसून में देरी या कम बारिश होने का सीधा असर फसल की बुवाई, खाद्यान्न की पैदावार, ग्रामीणों की आय और खाने-पीने की वस्तुओं की महंगाई के रूप में पड़ता है। ऐसे में यदि जुलाई व अगस्त माह के महत्वपूर्ण समय में बारिश सामान्य से कम होती है तो इसके परिणाम चिंता बढ़ाने वाले हो सकते हैं। केंद्र सरकार राज्य और जिले स्तर पर आपातकालीन योजनाएं तैयार कर रही है। सरकार सूखे में भी बेहतर उत्पादन कर सकने वाली फसलों को बढ़ावा देने के साथ ही जल संरक्षण पर जोर दे रही है।

साथ ही कोशिश है कि किसानों के लिये बीज-उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। देश में दालों, तिलहन और मोटे अनाजों की खेती को प्राथमिकता देना जरूरी है, क्योंकि ये फसलें कम पानी में भी सामान्य उत्पादन दे सकती हैं। सुखद ही है कि अल नीनो मॉनिटरिंग सेल को सक्रिय किया गया ताकि कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिये रियल-टाइम सलाह किसानों को देकर सूखे के प्रभावों को कम किया जा सके। निश्चित रूप से पूरी तैयारी के साथ सूखे से मुकाबले का मतलब है कि हमने आधी लड़ाई जीत ली है।

आज जरूरत इस बात की है कि सूखे की आशंका के बीच जल संकट से मुकाबले के लिये एक प्रभावी समग्र नीति बने। समय-समय पर इन नीतियों में सुधार किया जाए। जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन संकट के दौर में मानसून के व्यवहार में अनिश्चितता के बीच खेती की बारिश पर निर्भरता को कम करने के लिये व्यापक रणनीति तैयार की जाए। इसके लिये जरूरी है कि सूक्ष्म-सिंचाई सुविधा का विस्तार, जल निकायों के पुनरुद्धार, भूजल प्रबंधन को बेहतर बनाने और जलवायु के अनुरूप खेती को बढ़ावा देने के प्रयास हों। हम मौसम के बदलते मिजाज पर हर बार प्रतिक्रिया देने के बजाय दीघर्कालिक राष्ट्रीय प्राथमिकताएं सुनिश्चित करें।

हमें किसानों को आर्थिक संकट से उबारने को अपनी वरीयता सूची में शामिल करना चाहिए। विडंबना यह है कि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की रक्षा के लिये बीमा कवरेज अभी भी ज्यादा प्रभावी नहीं है। किसानों को फसलों को क्षति पहुंचने पर मुआवजा लेने के बारे में व्यावहारिक जानकारी अक्सर कम ही होती है। वैसे तो देश में अनाज का पर्याप्त भंडारण है और आपातकालीन व्यवस्था के चलते देश की खाद्य सुरक्षा को तुरंत कोई बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन हमें लाखों किसानों का जीविका संरक्षण भी प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में मौसम के मिजाज में होने वाला बदलाव अब कभी-कभार की बाधा नहीं रही, बल्कि बार-बार होने वाली सच्चाई बन गया है। मानसून के व्यवहार में लगातार अनिश्चितता को देखते हुए देश के नीति-निर्माताओं को खेती संरक्षण के लिये एक ऐसा तंत्र बनाने की जरूरत है, जो मौसम के बदलावों का बेहतर ढंग से मुकाबला कर सके। तभी हम भविष्य की अनिश्चितताओं का सही तरीके से सामना कर सकेंगे।

साथ ही हमें देश में पानी के सदुपयोग की दिशा में भी पहल करने की जरूरत है। देश में जलाशयों के जल का किफायती उपयोग हो। निस्संदेह, कम बारिश से केवल किसान व ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही प्रभावित नहीं होती है, सूखे में खाद्यान्न की उत्पादकता घटने पर अनाज महंगा होने से आम आदमी का जीवन भी बाधित होता है। जिससे किसान की ही नहीं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

सू- दोकू क्र.082

		3					7	
9				6		3		8
	7		9		5		6	
						1		9
3		8		7			5	
	1		3		9			7
		2		8		7		
	8				2		4	3
			1					

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.081 का हल

5	2	4	9	6	7	8	1	3
3	6	7	4	1	8	2	9	5
8	1	9	3	2	5	4	6	7
6	3	5	1	9	4	7	2	8
7	9	8	5	3	2	6	4	1
2	4	1	7	8	6	5	3	9
4	5	3	6	7	9	1	8	2
9	8	6	2	5	1	3	7	4
1	7	2	8	4	3	9	5	6

नई भाजपा के रोल माडल हैं योगी, हेमंत और शुभेंदु !

मोदी-शाह के नेतृत्व में सेकुलर संक्रमण से मुक्त हुई भारतीय राजनीति

संजय उवाच

प्रो. संजय द्विवेदी

उत्तर प्रदेश एक ऐसे मुख्यमंत्री से रूबरू है, जिसे राजनीति के मैदान में बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। उनके बारे में यह ख्यात था कि वे एक खास वर्ग की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी उनकी राजनीतिक शैली से पूरी तरह सहमत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह अपनी पकड़ बनाई है और देश में एक अलग माडल खड़ा दिया है, वह सर्वत्र चर्चा का विषय है। इससे यह भी साबित हो रहा है कि अपनी राजनीति के प्रति भाजपा का आत्मदैन्य कम हो रहा है। वहीं असम में हेमंत विश्वशर्मा उम्मीदों का चेहराबनकर उभरे हैं, असम में तीसरी बार सरकार बनाकर भाजपा ने पूर्वोत्तर में इतिहास रच दिया है। इसी तरह गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति से पश्चिम बंगाल की विजय ऐतिहासिक कही जा रही है और वहां बने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के ताबड़तोड़ फैसलों ने जनविश्वास की हिलोरें पैदा की हैं। जड़ता को तोड़कर एक नई उम्मीद बनी है। केंद्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आगमन ने भारतीय राजनीति के परिदृश्य को बदलकर रख दिया है।

वैचारिक हीनग्रंथि से बाहर आई भाजपा

भाजपा का आज तक का ट्रैक हिंदुत्व का वैचारिक और राजनीतिक इस्तेमाल कर सत्ता में आने का रहा है। देश की राजनीति में चल रहे विमर्श में भाजपा बड़ी चतुराई से इस कार्ड का इस्तेमाल तो करती थी, किंतु उसके नेतृत्व में इसे लेकर एक हिचक बनी रहती थी। वो हिचक अटल जी से लेकर आडवानी तक हर दौर में दिखी है। भाजपा का हर नेता सत्ता पाने के बाद यह साबित करने में लगा रहता है वह अन्य दलों के नेताओं के कम सेकुलर नहीं है। उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ परिघटना दरअसल भाजपा की वैचारिक हीनग्रंथि से मुक्ति को स्थापित करती नजर आती है। नरेंद्र मोदी के राज्यारोहण के बाद योगी आदित्यनाथ का उदय भारतीय राजनीति में एक अलग किस्म की राजनीति की स्वीकृति का प्रतीक है। एक धर्मप्राण देश में धार्मिक प्रतीकों, भगवा रंग, सन्यासियों के प्रति जैसी विरक्ति मुख्यधारा की राजनीति में दिखती थी, वह अन्यत्र दुर्लभ है। भाजपा जैसे दल भी इस सेकुलर विकार से कम ग्रस्त न थे। धर्म और धर्माचार्यों का इस्तेमाल, धार्मिक आस्था का दोहन और सत्ता पाते ही सभी धार्मिक प्रतीकों से मुक्ति लेकर सारी राजनीति सिर्फ तुष्टीकरण में लग जाती थी। प्रधानमंत्रियों समेत जाने कितने सत्ताधीशों के ताज जामा मस्जिद में झुके होगें, लेकिन हिंदुत्व के प्रति उनकी हिचक निरंतर थी।

यह भी कम आश्चर्यजनक नहीं की एक समय में दीनदयाल जी उदार थे, तो अटलजी और बलराज मधोक अपनी वक्रता के चलते उग्र नेता माने जाते थे। अटलजी का दौर आया तो लालकृष्ण आडवाणी उग्र कहे जाने लगे, फिर एक समय ऐसा भी आया जब आडवानी उदार हो गए और नरेंद्र मोदी उग्र मान जाने लगे। आज की व्याख्याएं सुनें- नरेंद्र मोदी उदार हो गए हैं और योगी आदित्यनाथऔर गृहमंत्री अमित शाह उग्र माने जाने लगे हैं। अब तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वशर्मा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी आदित्यनाथ की परंपरा के मुख्यमंत्री कहे जाने लगे हैं।

सेकुलर संक्रमण से मुक्ति से मिली नई पहचान

यह मीडिया, बौद्धिकों की अपनी रोज बनाई जाती व्याख्याएं हैं। लेकिन सच यह है कि अटल, मधोक, आडवानी, मोदी, अमित शाह या आदित्यनाथ, हेमंत विश्वशर्मा और शुभेंदु अधिकारी कोई अलग-अलग लोग नहीं है। एक विचार के प्रति समर्पित राष्ट्रनायकों की सूची है यह। इसमें कोई कम जा ज्यादा उदार या कठोर नहीं है। किंतु भारतीय राजनीति का विमर्श ऐसा है जिसमें वास्तविकता से अधिक ड्रामे पर भरोसा है। भारतीय राजनेता की मजबूरी है कि वह टोपी पहने, रोजा भले न रखे किंतु इफ्तार की दावतें दे। आप ध्यान दें सरकारी स्तर पर यह प्रहसन लंबे समय से जारी रहा है। भाजपा भी इसी राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है। उसमें भी इस तरह के रोग हैं। वह भी राष्ट्रनीति के साथ थोड़े तुष्टिकरण को गलत नहीं मानती। जबकि उसका अपना नारा रहा है सबको न्याय, तुष्टिकरण किसी का नहीं। उसका एक नारा यह भी रहा है-राम, रोटी और इंसाफ।

लंबे समय के बाद भाजपा में अपनी वैचारिक लाइन को लेकर गर्व का बोध दिख रहा है। असरे बाद वे भारतीय राजनीति के सेकुलर संक्रमण से मुक्त होकर अपनी वैचारिक भूमि पर गरिमा के साथ खड़े दिख रहे हैं। समझौतों और आत्मसमर्पण की मुद्राओं के बजाए उनमें अपनी वैचारिक भूमि के प्रति हीनताग्रंथि के भाव कम हुए हैं। अब वे अन्य दलों की नकल के बजाए एक वैचारिक लाइन लेते हुए दिख रहे हैं। दिखावटी सेकुलरिज्म के बजाए वास्तविक राष्ट्रीयता के उनमें दर्शन हो रहे हैं। मोदी जब एक सौ चालीस करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं तो बात अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक से ऊपर चली जाती है। यहां देश सम्मानित होता है, एक नई राजनीति का प्रारंभ दिखता है। एक भगवाधारी सन्यासी जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है तो वह एक नया संदेश देता है। वह संदेश त्याग का है, परिवारवाद के विरोध का है, तुष्टिकरण के विरोध का है, सबको न्याय का है।

भारतीयता का विमर्श अब केंद्रीय विमर्श

आजादी के बाद के सत्तर सालों में देश की राजनीति का विमर्श भारतीयता और उसकी जड़ों की तरफ लौटने के बजाए घोर पश्चिमी और वामपंथी रह गया था। जबकि बेहतर होता कि आजादी के बाद हम अपनी ज्ञान परंपरा की और लौटते और अपनी जड़ों को मजबूत बनाते। किंतु सत्ता,शिक्षा, समाज और राजनीति में हमने पश्चिमी तो, कहीं वामपंथी विचारों के आधार पर चीजें खड़ी कीं। इसके कारण हमारा अपने समाज से ही रिश्ता कटता चला गया। सत्ता और जनता की दूरी और बढ़ गयी। सत्ता दाता बन बैठी और जनता याचक। सेवक मालिक बन गए। ऐसे में लोकतंत्र एक छद्म लोकतंत्र बन गया। यह लोकतंत्र की विफलता ही है कि हम सत्तर साल के बाद सड़कें बना रहे हैं। यह लोकतंत्र की विफलता ही है कि हमारे अपने नौजवानों ने भारतीय राज्य के खिलाफ बंदूकें उठा रखी थीं। गृहमंत्री अमित शाह के दृढ़संकल्प की बदौलत आज माओवादी आतंक का अंत भी हमने देखा ।पिछले सत्तर सालों में लोकतंत्र की विफलता की ये कहानियां सर्वत्र बिखरी पड़ी हैं। राजनीतिक तंत्र के प्रति उठा भरोसा भी साधारण नहीं था। आज ऐसा लगता है कि राजनीति से कुछ हो सकता है। मोदी,शाह, आदित्यनाथ भरोसे के प्रतीक बन गए। इसका मतलब यह भी है कि ये कुछ कह रहे हैं तो करेंगें भी।

नरेंद्र मोदी, अमित शाह,आदित्यनाथ देश की इन्हीं उम्मीदों के चेहरे हैं। तीनों अंग्रेजी नहीं बोलते। तीनों जन-मन-गण के प्रतिनिधि हैं। यह भारतीय राजनीति का बदलता हुआ चेहरा है। क्या सच में भारत खुद को पहचान रहा है ? वह जातियों, पंथों, क्षेत्रों की पहचान से अलग एक बड़ी पहचान से जुड़ रहा है- वह पहचान है भारतीय होना, राष्ट्रीय होना। एक समय में राजनीति हमें नाउम्मीद करती हुयी नजर आती थी। बदले समय में वह उम्मीद जगा रही है। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो भरोसा जगाते हैं। एक आकांक्षावान भारत बनता हुआ दिखता है। यह आकांक्षाएं राजनीति दलों के एजेंडे से जुड़ पाएं तो देश जल्दी और बेहतर बनेगा। राजनीतिक विमर्श और जनविमर्श को साथ लाने की कवायद हमें करनी ही होगी। जल्दी बहुत जल्दी। यह जितना और जितना जल्दी होगा भारत अपने भाग्य पर इठलाता दिखेगा।

(लेखक राजनीतिक विश्वेषक और वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

वर्दी का भय या कानून का विश्वास ?

गोड्डा की एक घटना, पत्रकार सुरक्षा और झारखंड की कानून-व्यवस्था पर उठते गंभीर सवाल

विनोद कुमार सिंह

लोकतंत्र की सफलता केवल चुनावों, सरकारों और संवैधानिक संस्थाओं से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी आंकी जाती है कि आम नागरिक स्वयं को कितना सुरक्षित, सम्मानित और स्वतंत्र महसूस करता है। जब कोई नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता या पत्रकार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए भयमुक्त होकर प्रश्न पूछ सकता है, तभी लोकतंत्र वास्तव में जीवंत माना जाता है। लेकिन जब कानून की रक्षा करने वाली संस्थाओं पर ही भय पैदा करने के आरोप लगने लगें, तब लोकतंत्र के सामने गंभीर प्रश्न खड़े हो जाते हैं।

गोड्डा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लालपुर गाँव में 25 जून 2026 को सामने आई एक कथित घटना ने ऐसे ही अनेक सवालों को जन्म दिया है। आरोप है कि सादे वेश में कुछ पुलिसकर्मी बिना नंबर प्लेट वाले वाहन से गाँव पहुँचे और स्थानीय लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिसिया रौब दिखाया। आरोप यह भी है कि एक मान्यता प्राप्त पत्रकार द्वारा अपना परिचय पत्र दिखाने के बाद भी कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया गया। यद्यपि इन आरोपों की निष्पक्ष जाँच और पुलिस प्रशासन का पक्ष सामने आना अभी शेष है, फिर भी यह घटनाक्रम लोकतंत्र, पत्रकारिता और पुलिस जवाबदेही पर व्यापक चर्चा की माँग करता है।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या पत्रकार भीड़ का हिस्सा है? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से हृानहींह्व है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वह न सत्ता का प्रतिनिधि होता है और न ही विपक्ष का। उसका दायित्व जनता और शासन के बीच सूचना का सेतु बनना है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, पत्रकार उसी अधिकार का सामाजिक विस्तार है।

उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण से जुड़े पत्रकार पिछले लगभग तीन दशकों से देश की राजधानी दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं। वे अनेक राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पत्रकार संगठनों, प्रेस एसोसिएशनों तथा पत्रकार मंचों से जुड़े रहे हैं और जनसरोकार, प्रशासनिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा ग्रामीण भारत से जुड़े विषयों पर लगातार लेखन करते रहे हैं। ऐसे में यदि किसी वरिष्ठ और मान्यता प्राप्त पत्रकार के साथ भी कथित रूप से अभद्र व्यवहार या धमकी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो यह प्रश्न केवल एक व्यक्ति की गरिमा का नहीं रह जाता, बल्कि पत्रकारों की कार्य-स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा से भी जुड़ जाता है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक अवसरों पर कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है। यदि पत्रकार भयमुक्त नहीं रहेगा, तो जनता तक सत्य और सूचना का प्रवाह भी बाधित होगा। इसलिए किसी पत्रकार के साथ कथित दुर्व्यवहार केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रता से जुड़ा विषय बन जाता है। दूसरी ओर यह भी उतना ही सत्य है कि पुलिस व्यवस्था किसी भी राज्य की रीढ़ होती है। झारखंड जैसे राज्य में पुलिस की भूमिका और भी चुनौतीपूर्ण है। राज्य लंबे समय तक नक्सलवाद, संगठित अपराध, अवैध खनन, साइबर अपराध तथा सामाजिक तनावों जैसी समस्याओं से जूझता रहा है। हाल के वर्षों में झारखंड पुलिस ने अपराध नियंत्रण और उग्रवाद विरोधी अभियानों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। अपराधियों की गिरफ्तारी, अवैध हथियारों की बरामदगी और साइबर अपराध के विरुद्ध कार्रवाई पुलिस की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही हैं।

गोड्डा जिला भी इससे अछूता नहीं है। जिले में समय-समय पर अवैध हथियारों, आपराधिक गिरोहों, भूमि विवादों तथा संगठित अपराधों के विरुद्ध अभियान चलाए जाते रहे हैं। ऐसे में पुलिस को कई बार त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन लोकतंत्र में किसी भी कार्रवाई की वैधता केवल उसके उद्देश्य से नहीं, बल्कि उसकी प्रक्रिया से भी तय होती है।

यही वह बिंदु है जहाँ नागरिक अधिकारों और पुलिस शक्तियों के बीच संतुलन आवश्यक हो जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जा सकता। यदि पुलिस पूछताछ करती है तो नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि उससे पूछताछ करने वाला व्यक्ति कौन है और किस अधिकार के तहत कार्रवाई कर रहा है। सवाल यह भी है कि यदि पुलिस सादे वेश में कार्रवाई कर रही हो तो उसकी पहचान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? आज के दौर में जब अपराधी भी स्वयं को पुलिस बताकर लोगों को ठगने लगे हैं, तब आम नागरिक के मन में संदेह होना स्वाभाविक है। इसलिए पारदर्शिता केवल नागरिक का अधिकार नहीं, बल्कि पुलिस प्रशासन की भी आवश्यकता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आँकड़े बताते हैं कि झारखंड के सामने अपराध नियंत्रण की चुनौती अभी भी बनी हुई है। हत्या, साइबर अपराध, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और आर्थिक अपराध जैसी समस्याएँ राज्य के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस को अधिक अधिकार और संसाधन मिलना चाहिए, लेकिन उतनी ही मजबूती से जवाबदेही की व्यवस्था भी सुनिश्चित होनी चाहिए। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। यह सिद्धांत नागरिक पर भी लागू होता है और वर्दी पर भी। पुलिस की शक्ति संविधान से आती है, भय से नहीं। यदि किसी नागरिक या पत्रकार को यह महसूस हो कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो उसे शिकायत करने, जाँच की माँग करने और न्याय पाने का अधिकार है।

आज आवश्यकता पुलिस बनाम पत्रकार की बहस की नहीं है। आवश्यकता पुलिस और पत्रकार के बीच विश्वास बहाली की है। दोनों ही लोकतंत्र की सेवा कर रहे हैं। पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करती है और पत्रकार उस कार्रवाई को जनता तक पहुँचाता है। दोनों का लक्ष्य अंततः जनहित ही है। यदि लालपुर की घटना में लगाए गए आरोप गलत सिद्ध होते हैं, तो इससे पुलिस की प्रतिष्ठा और मजबूत होगी। यदि कहीं किसी स्तर पर चूक या दुर्व्यवहार पाया जाता है, तो निष्पक्ष कार्रवाई से जनता का विश्वास बढ़ेगा। दोनों ही परिस्थितियों में सत्य, पारदर्शिता और विधि का शासन ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है।

झारखंड पुलिस के हजारों अधिकारी और जवान कठिन परिस्थितियों में दिन-रात सेवा दे रहे हैं। उनके योगदान का सम्मान होना चाहिए। लेकिन उतना ही आवश्यक यह भी है कि आम नागरिक, पत्रकार और समाज के कमजोर वर्ग स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। लोकतंत्र में वर्दी का सम्मान और नागरिक की गरिमा—दोनों साथ-साथ चलते हैं। कानून का राज केवल अपराधियों को पकड़ने से स्थापित नहीं होता। कानून का राज तब स्थापित होता है जब आम आदमी बिना भय के अपने अधिकारों का उपयोग कर सके, पत्रकार बिना दबाव के प्रश्न पूछ सके और पुलिस बिना पक्षपात के कानून लागू कर सके। गोड्डा की यह कथित घटना चाहे जिस निष्कर्ष तक पहुँचे, उसने एक महत्वपूर्ण प्रश्न अवश्य खड़ा किया है—क्या हम भय आधारित व्यवस्था चाहते हैं या विश्वास आधारित शासन?

लोकतंत्र का उत्तर स्पष्ट है। वर्दी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन संविधान उससे भी ऊपर है। पत्रकार का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वह जनता की आवाज है। और सबसे बढ़कर, आम नागरिक का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वही लोकतंत्र का वास्तविक स्वामी है। जब वर्दी में संवेदनशीलता होगी, कलम में निर्भीकता होगी और नागरिक के मन में विश्वास होगा, तभी झारखंड की कानून-व्यवस्था वास्तव में मजबूत मानी जाएगी। यही लोकतंत्र की आत्मा है, यही संविधान की भावना है और यही भारत की सबसे बड़ी शक्ति भी।

मादक पदार्थों का बढ़ता साम्राज्य और सिमटते सपने

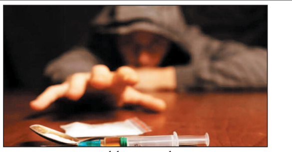

योगेश कुमार गोयल

भारत आज जिस सबसे खतरनाक सामाजिक संकट का सामना कर रहा है, वह केवल नशे की बढ़ती प्रवृत्ति नहीं बल्कि युवा सोच पर पड़ता उसका गहरा ग्रहण है। नशा केवल शरीर को नहीं, सपनों, प्रतिभा और राष्ट्र की संभावनाओं को भी खोखला कर रहा है। ऐसे में नशा-मुक्त भारत का संकल्प पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा एवं मादक पदार्थ निषेध दिवस मनाया जाता है, जो इसी त्रासदी की याद दिलाता है, जो आज हमारे समाज, विशेषकर युवाओं की नसों में जहर बनकर दौड़ रही है।

किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी के सपनों, ऊर्जा और सृजनशीलता पर निर्भर करता है लेकिन जब यही युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आने लगे तो यह केवल एक सामाजिक समस्या नहीं रह जाती बल्कि राष्ट्रीय संकट का रूप धारण कर लेती है। आज भारत सहित दुनिया के अनेक देशों के सामने यही चुनौती खड़ी है। युवाओं की प्रतिभा, उनकी सोच, उनकी रचनात्मकता और उनके भविष्य पर नशे का ऐसा ग्रहण लग रहा है, जो न केवल परिवारों को बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को भीतर से खोखला कर रहा है। इसी गंभीर चुनौती के प्रति वैश्विक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा एवं मादक पदार्थ निषेध दिवस मनाया जाता है। यह दिवस केवल औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि पूरी मानवता को चेताने का अवसर है कि यदि नशे के बढ़ते दुष्चक्र को समय रहते नहीं रोका गया तो इसके परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतने पड़ेंगे।

भारत में नशे की समस्या अब महानगरों तक सीमित नहीं रही। यह गांवों, कस्बों, छोटे शहरों और यहां तक कि स्कूलों तथा कॉलेजों तक पहुंच चुकी है। कभी माना जाता था कि नशीले पदार्थों का सेवन केवल संपन्न वर्ग या शहरी संस्कृति की समस्या है लेकिन आज वास्तविकता इससे कहीं अधिक भयावह है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अफीम, चरस, गांजा, हेरोइन, सिंथेटिक ड्रग्स और इंजेक्शन के माध्यम से लिए जाने वाले नशीले पदार्थों का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। यह स्थिति बताती है कि नशे का नेटवर्क अब समाज की हर परत तक पहुंच चुका है। आज का युवा अनेक प्रकार के दबावों से घिरा हुआ है। प्रतिस्पर्धा, बेरोजगारी, सामाजिक अपेक्षाएं, पारिवारिक तनाव, मानसिक अवसाद, अकेलापन और त्वरित सफलता की चाह उसे भीतर से कमजोर बना रही है। ऐसे में नशे के सौदागर युवाओं की इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। कई बार मित्रों का दबाव, आधुनिक दिखने की चाह, रोमांच की तलाश या क्षणिक सुख का आकर्षण युवाओं को नशे की ओर धकेल देता है। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है लेकिन धीरे-धीरे यही जिज्ञासा लत और फिर विनाश का कारण बन जाती है।

इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने जहां ज्ञान के नए द्वार खोले हैं, वहीं नशे के कारोबार को भी नए साधन उपलब्ध कराए हैं। सोशल मीडिया, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स और डार्क वेब के माध्यम से मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है। अब नशे का सौदा किसी सुनसान गली तक सीमित नहीं बल्कि स्माटफीन की स्क्रीन तक पहुंच चुका है। यही कारण है कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नशे की पहुंच चिंताजनक रूप से बढ़ती जा रही है। आज देश के अनेक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में नशीले पदार्थों की उपलब्धता को लेकर समय-समय पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। यह विडंबना ही है कि जिन परिसरों में देश के भविष्य का निर्माण होना चाहिए, वहां कुछ युवा अपने भविष्य को स्वयं नष्ट करने की राह पर बढ़ रहे हैं। आधुनिकता और स्वतंत्रता की गलत व्याख्या ने भी इस समस्या को बढ़ाया है। कई युवाओं को यह भ्रम होता है कि नशा उन्हें अधिक आत्मविश्वासी, रचनात्मक और आधुनिक बनाता है, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। नशा व्यक्ति की सोचने-समझने की क्षमता को धीरे-धीरे समाप्त कर देता है। उसकी निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो जाती है, स्मरणशक्ति प्रभावित होती है, एकाग्रता घटती है और मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। जो युवा अपने जीवन में बड़े सपने लेकर आगे बढ़ता है, वही नशे की गिरफ्त में आकर अपनी प्रतिभा और संभावनाओं को स्वयं नष्ट कर देता है। यही कारण है कि नशे को केवल स्वास्थ्य समस्या नहीं बल्कि मानव संसाधन के विनाश की समस्या माना जाता है।

नशीले पदार्थों का सबसे घातक प्रभाव यह है कि वे व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से गुलाम बना देते हैं। एक बार लत लग जाने पर व्यक्ति उसी प्रभाव को बनाए रखने के लिए लगातार अधिक मात्रा में नशा लेने लगता है। परिणामस्वरूप उसका शरीर कमजोर होने लगता है, भूख कम हो जाती है, वजन घटता है, आंखें लाल रहने लगती हैं, नींद प्रभावित होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई मामलों में व्यक्ति आत्मघाती प्रवृत्तियों का शिकार भी हो जाता है। इंजेक्शन के माध्यम से नशा करने वालों के सामने खतरा और भी गंभीर होता है। एक ही सुई के बार-बार उपयोग से एचआईवी, हेपेटाइटिस और अन्य संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ जाती है। यही कारण है कि नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती बन जाता है।

नशे का अवैध व्यापार दुनिया के सबसे लाभकारी अपराधों में शामिल है। अरबों-खरबों रुपये का यह कारोबार अंतर्राष्ट्रीय तस्करी, आतंकवाद, संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों से गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत की भौगोलिक स्थिति इसे गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल जैसे नशीले पदार्थों के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों के बीच महत्वपूर्ण मार्ग बनाती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों से आने वाली तस्करी की खेपें भारत के लिए लगातार चुनौती बनी हुई हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ड्रग्स का यह अवैध कारोबार अब अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहा है। ड्रोन, एन्क्रिप्टेड संचार माध्यम, फर्जी पहचान और डिजिटल भुगतान प्रणालियां तस्करों को नई ताकत प्रदान कर रही हैं। ऐसे में केवल पारंपरिक पुलिसिंग से इस समस्या पर नियंत्रण संभव नहीं है। इसके लिए तकनीकी, सामाजिक और कानूनी स्तर पर व्यापक रणनीति की आवश्यकता है।

भारत में हालांकि मादक पदार्थों की तस्करी और सेवन को रोकने के लिए कड़े कानून मौजूद हैं लेकिन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की चुनौती अभी भी बनी हुई है। नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस, प्रशासन या सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, यह समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। परिवारों को अपने बच्चों के साथ संवाद बढ़ाना होगा। शिक्षण संस्थानों को नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाने होंगे। धार्मिक और सामाजिक संगठनों को भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। दरअसल नशे के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार जागरूकता, शिक्षा और सकारात्मक वातावरण है। यदि युवाओं को बेहतर शिक्षा, रोजगार, खेल, कला, संस्कृति और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा जाए तो वे नशे जैसे विनाशकारी रास्तों से दूर रह सकते हैं। हमें युवाओं को केवल नशे के दुष्परिणाम बताने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि उन्हें जीवन का सकारात्मक उद्देश्य भी देना होगा।

अंतर्राष्ट्रीय नशा एवं मादक पदार्थ निषेध दिवस हमें यही संदेश देता है कि नशे के खिलाफ लड़ाई किसी एक दिन का अभियान नहीं बल्कि सतत सामाजिक आंदोलन है। यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले उसकी युवा शक्ति को नशे के अंधकार से मुक्त करना होगा। देश की युवा सोच पर लगा यह ग्रहण तभी हटेगा, जब सरकार, समाज, परिवार और स्वयं युवा मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि युवाओं के हाथों में नशे की पुड़िया नहीं, ज्ञान की पुस्तक हो; उनकी आंखों में नशे का धुंधलापन नहीं, सपनों की चमक हो; और उनकी सोच पर नशे का ग्रहण नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का उज्ज्वल प्रकाश हो। यही नशा-मुक्त भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता है और यही विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव भी।

छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के 2 साल बेमिसाल, तीसरा साल बनेगी एक नई मिसाल

जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क से 'ऑपरेशन गोल्ड' तक : कल बिलासपुर में सजेगा प्रदेश स्तरीय 'सराफा महासम्मेलन' का भव्य मंच

नई दृष्टिबिंदु / बिलासपुर

छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी के कुशल नेतृत्व में अपने सफल एवं ऐतिहासिक दो वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस दौरान संगठन ने सराफा व्यापारियों के हितों की रक्षा, संगठनात्मक विस्तार, सुरक्षा, जागरूकता, डिजिटल सशक्तिकरण तथा व्यापारिक विकास के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। संगठन ने प्रदेशभर के छोटे-बड़े सराफा व्यापारियों को एक सशक्त मंच पर जोड़ने का कार्य किया है और अब तीसरे वर्ष में नई उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया है।

शुक्रवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में आयोजित राज्य स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के दो वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित विशेष छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में सराफा जन-संवाद अभियान, संगठन विस्तार, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ऑपरेशन गोल्ड, बीआईएस जागरूकता अभियान तथा संगठन की अन्य प्रमुख उपलब्धियों को मीडिया एवं आमजन के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

रविवार को प्रातः 10 बजे से रामदेव लॉन, 36 मॉल के बगल, मंगला, बिलासपुर में प्रदेश स्तरीय सराफा महासम्मेलन एवं तृतीय आमसभा आयोजित होगी। इससे पूर्व संगठन की आमसभाएँ जगदलपुर एवं जांजगीर में सफलतापूर्वक आयोजित हो चुकी हैं तथा इस बार न्यायधानी बिलासपुर को इस भव्य आयोजन की मेजबानी का अवसर प्राप्त हुआ है। महासम्मेलन में प्रदेशभर से लगभग 5,000 सराफा व्यापारी, प्रतिनिधि एवं पदाधिकारी शामिल होंगे।

ऑपरेशन गोल्ड : पुलिस-व्यापारी समन्वय की मिसाल

बिलासपुर पुलिस द्वारा संचालित 'ऑपरेशन गोल्ड' पुलिस एवं सराफा व्यापारियों के बीच उत्कृष्ट समन्वय का प्रतीक बनकर सामने आया। सरकंडा क्षेत्र में हुई डकैती की घटना के मात्र 24 घंटे के भीतर बिलासपुर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर एक नई मिसाल कायम की। इस उल्लेखनीय सफलता के लिए आईजी रामगोपाल गर्ग, एसएसपी रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, मीरजपुर तक गई विशेष पुलिस टीम के टीम लीडर सीएसपी निमितेश सिंह तथा पूरी पुलिस टीम का छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन द्वारा सम्मान कर आभार व्यक्त किया गया। प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी ने कहा कि पिछले दो वर्षों में पूरे प्रदेश के पुलिस अधिकारियों ने सराफा व्यापारियों की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में अत्यंत सार्थक सहयोग प्रदान किया है, जिसके लिए संगठन उनका हृदय से आभारी है।

सुरक्षा व जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य

पिछले दो वर्षों में संगठन ने ग्राहक जागरूकता अभियान, बीआईएस हॉलमार्क जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यशालाओं तथा सराफा जन-संवाद अभियान के माध्यम से व्यापारियों और ग्राहकों के बीच विश्वास बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी ने ग्राहकों से केवल बीआईएस हॉलमार्क युक्त आभूषण खरीदने तथा स्थानीय विश्वसनीय सराफा व्यापारियों पर विश्वास बनाए रखने की अपील की।

संगठन विस्तार की ऐतिहासिक यात्रा

प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी ने बताया कि जनवरी 2024 में प्रदेश में संगठन की लगभग 60 सक्रिय इकाइयाँ थीं। संगठन विस्तार अभियान के परिणामस्वरूप जून 2024 तक यह संख्या बढ़कर 91 से अधिक हो गई तथा वर्तमान में प्रदेशभर में 125 से अधिक इकाइयाँ संगठन से जुड़ चुकी हैं। उन्होंने बताया कि संगठन का संकल्प प्रदेश के प्रत्येक सराफा व्यापारी को एक सशक्त मंच से जोड़ते हुए 251 इकाइयों का गठन करना है। इसी उद्देश्य से सभी संभागों में आमसभाओं का आयोजन, संभागीय प्रतिनिधियों की नियुक्ति तथा निरंतर जन-संवाद एवं संगठन विस्तार अभियान संचालित किए जा रहे हैं। संगठन के इस व्यापक विस्तार अभियान ने पूरे प्रदेश के सराफा व्यापारियों में एकता, विश्वास एवं सहभागिता को और अधिक मजबूत किया है।

जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क : ऐतिहासिक उपलब्धि

दो वर्षीय कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में रायपुर में प्रस्तावित जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क को शासन स्तर पर स्वीकृति दिलाने की दिशा में हुई महत्वपूर्ण प्रगति शामिल है। संगठन का मानना है कि यह परियोजना छत्तीसगढ़ के सराफा उद्योग को नई पहचान प्रदान करेगी। प्रस्तावित पार्क में आधुनिक कार्यालय, सामुदायिक भवन तथा व्यापारिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। सामाजिक एवं सांस्कृतिक सहभागिता

व्यापारिक गतिविधियों के साथ-साथ संगठन सामाजिक एवं सांस्कृतिक दायित्वों के निर्वहन में भी सक्रिय रहा है। विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों में सहभागिता के साथ-साथ संगठन ने समाजहित के अनेक कार्यों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है।

महासम्मेलन का प्रमुख विषय : धारा 317 का सरलीकरण

28 जून को आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय सराफा महासम्मेलन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 के सरलीकरण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। इस धारा के कारण सराफा व्यापारियों को हो रही व्यावहारिक एवं कानूनी कठिनाइयों पर विस्तार से चर्चा कर शासन से सरल, स्पष्ट एवं व्यावहारिक नियम बनाए जाने की मांग की जाएगी।

भविष्य की दिशा

संगठन का उद्देश्य केवल संगठन विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि सराफा व्यापारियों की सुरक्षा, व्यापारिक हितों की रक्षा, आधुनिक व्यापारिक सुविधाओं का विकास, स्वर्णकला बोर्ड की स्थापना तथा प्रदेश के प्रत्येक व्यापारी को एक मजबूत एवं प्रभावशाली मंच उपलब्ध कराना है।

प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी का संदेश

"हमारे दो वर्ष उपलब्धियों से परिपूर्ण रहे हैं। संगठन ने व्यापारियों को एक नई पहचान और मजबूती दी है। अब हमारा लक्ष्य 251 इकाइयों का गठन, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना, व्यापारियों की सुरक्षा को और मजबूत करना तथा बीएनएस की धारा 317 का सरलीकरण सुनिश्चित करना है। हमें विश्वास है कि तीसरा वर्ष संगठन के लिए नई मिसाल स्थापित करेगा।"

महासम्मेलन की तैयारियाँ अंतिम चरण में

प्रदेश स्तरीय सराफा महासम्मेलन एवं तृतीय आमसभा की तैयारियाँ अंतिम चरण में हैं। आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी के नेतृत्व में प्रदेश सचिव प्रकाश गोलछा, प्रदेश कोषाध्यक्ष हर्षवर्धन जैन, अध्यक्ष अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं समन्वयक प्रदीप मारोठी घोरपड़े, कार्यकारी अध्यक्ष संजय कानुगा (रायपुर संभाग), उत्तमचंद भंडारी (दुर्ग संभाग), पवन अग्रवाल (बिलासपुर संभाग), राजू दुग्गड़ (बस्तर संभाग), राजेश सोनी (सरगुजा संभाग), संगठन मंत्री सुनील सोनी, मीडिया प्रभारी आलोक सोनी, जिला अध्यक्ष कल्याण सिंह, जिला सचिव दीपक सोनी एवं कार्यकारी अध्यक्ष श्रीकांत पाण्डेय सहित प्रदेश एवं जिला स्तर के पदाधिकारी सक्रिय रूप से तैयारियों में जुटे हुए हैं। आयोजन समिति में पंकज करैख, राजेश शाह, अजय सराफ, प्रमोद वर्मा, नवनाथ आवले, सूरज सोनी, शशांक स्वर्णकार, राजू पारेख एवं सज्जन सोनी विभिन्न व्यवस्थाओं का दायित्व निभाते हुए आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इस भव्य प्रदेश स्तरीय आयोजन को सफल बनाने में बिलासपुर सराफा एसोसिएशन, बिलासपुर सिल्वर होलसेल सराफा एसोसिएशन, तखतपुर सराफा एसोसिएशन, सीपत सराफा एसोसिएशन, मरवाही सराफा एसोसिएशन, बेलतरा सराफा एसोसिएशन, चकरभाठा सराफा एसोसिएशन, करगी रोड-कोटा सराफा एसोसिएशन, बिल्हा-सरगांव सराफा एसोसिएशन एवं रतनपुर सराफा एसोसिएशन की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रहेगी।

आयोजन समिति में पंकज पारेख, राजेश शाह, अजय सराफ, प्रमोद वर्मा, नवनाथ आवले, सूरज सोनी, शशांक स्वणर्कार, राजू पारेख एवं सज्जन सोनी विभिन्न व्यवस्थाओं का दायित्व निभाते हुए आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस भव्य प्रदेश स्तरीय आयोजन को सफल बनाने में बिलासपुर सराफा एसोसिएशन, बिलासपुर सिल्वर होलसेल सराफा एसोसिएशन, तखतपुर सराफा एसोसिएशन, सीपत सराफा एसोसिएशन, मरवाही सराफा एसोसिएशन, बेलतरा सराफा एसोसिएशन, चकरभाठा सराफा एसोसिएशन, करगी रोड-कोटा सराफा एसोसिएशन, बिल्हा-सरगांव सराफा एसोसिएशन एवं रतनपुर सराफा एसोसिएशन की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रहेगी। प्रेस वार्ता में कल्याण सोनी, श्रीकांत पाण्डेय, प्रमोद वर्मा, सजन सोनी, नवनाथ, अजय सराफ आदि सराफा व्यवसाई मौजूद थे।

खास खबर

केन्द्रीय जेल दुर्ग में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन संपन्न

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

केंद्रीय जेल दुर्ग में आज बंदियों के पुनर्वास एवं समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से "नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम" का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बंदियों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराना तथा उन्हें स्वस्थ, अनुशासित एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था।

कार्यक्रम में हिमांशु जैन, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय जिला दुर्ग द्वारा नशे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं पारिवारिक दुष्प्रभावों पर विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही नशे से मुक्ति के प्रभावी उपाय, परामर्श (काउंसलिंग) तथा आत्मविश्वास एवं इच्छाशक्ति के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर बंदियों ने नशामुक्त जीवन अपनाने एवं समाज में लौटकर जिम्मेदार नागरिक के रूप में जीवन व्यतीत करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें बंदियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।

जेल प्रशासन द्वारा बताया गया कि बंदियों के सर्वांगीण विकास एवं सफल पुनर्वास के लिए समय-समय पर ऐसे जागरूकता कार्यक्रम, योग, ध्यान, कौशल विकास एवं परामर्श गतिविधियों का आयोजन निरंतर किया जाता है। इस प्रयासों का उद्देश्य बंदियों में समारात्मक सोच विकसित करना तथा उन्हें अपराध एवं नशे से दूर रखते हुए समाज की मुख्यधारा में पुनर्स्थापित करना है। "नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम" के आयोजन में जेल अधीक्षक मनीष सम्भाकर, एवं अन्य जेल स्टॉफ उपस्थित रहें।

बीएसपी की आरएसएम में क्रेन ऑपरेटरों के लिए नया लैंडिंग प्लेटफॉर्म किया गया शुरू

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र की रेल एवं स्ट्रक्चरल मिल (आरएसएम) में कार्यस्थल सुरक्षा मजबूत करने के लिए बुधवार को बीसी बे, हॉट सॉ पल्पिट क्रमांक-9 के पास क्रेन ऑपरेटरों के लिए नवीन लैंडिंग प्लेटफॉर्म का लोकार्पण किया गया। मुख्य महाप्रबंधक तीर्थंकर दस्तिदार ने वरिष्ठ अधिकारियों और विभागीय टीम की मौजूदगी में प्लेटफॉर्म का लोकार्पण किया। इस मौके पर महाप्रबंधक अरविंद टंडन, महाप्रबंधक एन.के. खरे, प्रशांत खोंड, आर.के. राजधर, महाप्रबंधक प्रशांत लाखे समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

पुराना प्लेटफॉर्म था क्षतिग्रस्त, बढ़ रहा था खतरा : पूर्व में इस स्थान पर बना लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्षतिग्रस्त और अनुपयोगी हो गया था। इससे क्रेन तक सुरक्षित पहुंच नहीं हो पा रही थी। बार-बार क्रेन की री-पोजिशनिंग करनी पड़ती थी, जिससे परिचालन में सुरक्षा चुनौतियां आ रही थीं। आरएसएम के यांत्रिक विभाग ने समस्या की पहचान कर पुराने प्लेटफॉर्म को हटाकर नया प्लेटफॉर्म बनाने का निर्णय लिया।

दो सप्ताह में तैयार, उत्पादन भी नहीं रुका : लगभग 12 से 13 मीटर लंबे इस नए लैंडिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए मात्र दो सप्ताह में पूरा किया गया। खास बात यह रही कि निर्माण के दौरान उत्पादन गतिविधियां निर्बाध रूप से चलती रहीं। नए प्लेटफॉर्म से अब क्रेन ऑपरेटर सुरक्षित और आसानी से क्रेन तक पहुंच सकेंगे। इससे कार्यस्थल की सुरक्षा के साथ परिचालन दक्षता भी बढ़ेगी।

भाजपा कार्यालय में आपातकाल को भाजपा ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया

मीसाबंदियों का सम्मान, संगोष्ठी का आयोजन, विरोध में निकाली मौन रैली

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

भारतीय जनता पार्टी जिला दुर्ग द्वारा 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की 51वीं बरसी के अवसर पर जिला भाजपा कार्यालय में संविधान हत्या दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने की। इस अवसर पर आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले मीसाबंदियों का सम्मान किया गया तथा विषय आधारित संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम के बाद भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की रक्षा का संदेश देते हुए मौन रैली निकाली।

कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं मुख्य वक्ता शिरीष अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव, विधायक ललित चंद्राकर, महापौर अलका बाघमार, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य माया बेलचंदन, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन, आर्थिक प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक शिव चंद्राकर, जिला महामंत्री दिलीप साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक ऐसा दौर था, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई और नागरिक अधिकारों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि नई पीढ़ी को उस दौर के इतिहास से अवगत होना चाहिए।

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य शिरीष अग्रवाल ने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है और लोकतांत्रिक संस्थाओं एवं संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के प्रति समाज को सतत सजग रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष को स्मरण करना है।

जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने कहा कि यह आयोजन केवल इतिहास को याद करने का अवसर नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराने का भी अवसर है। इस अवसर पर मीसाबंदी राम पाटणकर ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान अनेक लोगों ने जेल में कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी।

कार्यक्रम के पश्चात जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक के नेतृत्व में मौन रैली निकाली गई। रैली जिला भाजपा कार्यालय से प्रारंभ होकर शनिचरी बाजार, कांग्रेस भवन, सदर बाजार, गांधी चौक और जवाहर चौक होते हुए पुनः जिला भाजपा कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संदेश दिया। आयोजित संगोष्ठी एवं रैली में भाजपा पदाधिकारी, विभिन्न मोर्चों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

---

65 साल से चली आ रही परंपरा कायम, मोहर्रम पर दस रोजा मजलिस का आयोजन

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

अंजुमन इस्लाहुल मुस्लेमीन कमेटी, दुर्ग की ओर से मोहर्रम-उल-हराम के मौके पर शोहदाए कबर्ला की याद में आयोजित दस रोजा मजलिस एवं तकरीर का सिलसिला इस साल भी पूरी अकीदत के साथ संपन्न हुआ। कमेटी पिछले 65 वर्षों से यह आयोजन करती आ रही है। कमेटी के अध्यक्ष सैय्यद आसिफ अली एवं प्रवक्ता सैय्यद अनीस रजा ने बताया कि इस वर्ष कानपुर से आए मशहूर मुक़र्रिर हजरत अल्लामा मौलाना खलीफा-ए-सरकार-ए-कला हाशिम कानपुरी साहब ने लगातार दस दिनों तक इल्मी और रूहानी बयानात से श्रोताओं को संबोधित किया।

अपने खिताब में मौलाना हाशिम कानपुरी ने कबर्ला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन (अ.स.) और उनके साथियों की कुर्बानियों को याद किया। उन्होंने कहा कि इंसानियत, सच्चाई, इंसाफ, सब्र और जुल्म के खिलाफ खड़े होने का पैगाम ही कबर्ला का असली संदेश है। मौलाना ने देश में अमन, भाईचारे, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की और सभी नागरिकों से राष्ट्रीय एकता मजबूत करने की अपील की।

मौलाना ने मुसलमानों से कुरआन व सुन्नत की तालीमात पर अमल करते हुए अच्छे अखलाक, ईमानदारी, शिक्षा और सामाजिक सेवा में आगे आने को कहा। उन्होंने कहा, एक अच्छा मुसलमान वही है जो अपने किरदार से मोहब्बत, अमन, इंसाफ और इंसानियत का पैगाम फैलाए और सभी धर्मों के लोगों से भाईचारे का व्यवहार करे। अंजुमन कमेटी ने सफल आयोजन के लिए उलेमा, मेहमानों, पदाधिकारियों, वालंटियर्स, मीडिया और नगरवासियों का शुक्रिया अदा किया। कमेटी ने कहा कि भविष्य में भी कौमी एकता और इंसानियत का पैगाम फैलाने के लिए ऐसे धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रम होते रहेंगे।

"महिला सशक्तिकरण से ही बनेगा सशक्त भारत, भाजपा की असली ताकत है नारी शक्ति"

अंजोरा मंडल महिला मोर्चा का परिचयात्मक सम्मेलन और सम्मान समारोह गरिमामय रूप से संपन्न

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

भारतीय जनता पार्टी अंजोरा मंडल द्वारा नवनियुक्त महिला मोर्चा कायर्कारिणी का परिचयात्मक सम्मेलन एवं सम्मान समारोह आज ग्राम नगपुरा स्थित रेस्ट हाउस में हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक ललित चंद्राकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे एवं नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं प्रदान की।

कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीमती तृप्ति चंद्राकर ने अंजोरा मंडल की नवनियुक्त टीम का परिचय कराया एवं सभी का स्वागत किया। विधायक ललित चंद्राकर ने अपने ओजस्वी संबोधन में कहा "भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और इसकी रीढ़ हमारी मातृशक्ति है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' लाकर महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक कार्य किया है। 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ', 'उज्ज्वला योजना', 'मुद्रा योजना' से लेकर 'लखपति दीदी' तक, हर योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर है।" मुझे पूर्ण विश्वास है कि अंजोरा मंडल की नवनियुक्त महिला मोर्चा टीम प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत 2047' के संकल्प को धरातल पर साकार करेगी। आप सभी बहनें केंद्र व छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर पर बैठी माता-बहनों तक पहुंचाने का कार्य करें। नारी शक्ति का संगठन में सक्रिय योगदान भाजपा को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत करेगा।"

श्री चंद्राकर ने आगे कहा कि "डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ तेजी से विकास कर रहा है। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की सम्मान राशि मिल रही है। महिला मोर्चा की जिम्मेदारी है कि एक भी पात्र बहन योजना से वंचित न रहे।" उन्होंने संगठन को और अधिक सशक्त बनाने हेतु एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। अंजोरा मंडल अध्यक्ष हेमंत सिन्हा ने कहा कि महिला मोर्चा के गठन से मंडल संगठन को नई ऊर्जा मिली है और आगामी सभी कार्यक्रमों में महिला मोर्चा की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीमती तृप्ति चंद्राकर, जिला महामंत्री श्रीमती ममता राव, जिला मंत्री गिरेश साहू, अंजोरा मंडल अध्यक्ष हेमंत सिन्हा, मंडल महामंत्री श्रीमती यामिनी हरमुख, जनपद अध्यक्ष श्रीमती कुलेश्वरी देवांगन, जिला पंचायत सभापति सुश्री प्रिया साहू, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्रीमती रामकली साहू, मंडल महामंत्री श्रीमती भू भारती, श्रीमती बीणा महतेल, सरपंच संघ अध्यक्ष राजू यादव, वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमती शिव कुमारी वैष्णव, पूर्व जनपद सदस्य श्रीमती भाना बाई ठाकुर, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष विनोद साहू, मंडल उपाध्यक्ष नंदू निर्मलकर, मंडल मंत्री झमनेस देशमुख,

नेगेटिव कमेंट्स का असर खुद पर नहीं पड़ने देता

अभिनेता अनुपम खेर ने सफलता, दृढ़ता और आलोचना का सामना करने के बारे में एक प्रेरक संदेश शेयर किया है। हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में अनुपम खेर बताया कि अब वे नेगेटिव कमेंट्स का खुद पर असर नहीं पड़ने देते। चुनौतियों के प्रति अपने जीवनभर के लगाव के बारे में बात करते हुए खेर ने कहा कि असली खुशी सिर्फ शिखर पर पहुंचने में नहीं, बल्कि मुश्किलों को पार करने के सफर में मिलती है। अपनी कई तस्वीरें शेयर करते हुए 'तन्वी द ग्रेट' के एक्टर ने लिखा, 'मुझे हमेशा से चढ़ाई करना पसंद रहा है। इसलिए नहीं कि मैं शिखर पर पहुंचना चाहता हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे चढ़ाई की चुनौती पसंद है। रास्ता जितना मुश्किल होता है, ऐसी जगह पहुंचने पर उतनी ही अधिक खुशी मिलती है, जहां पहुंचने की आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। हां, जब आप किसी खास मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तो हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो आपको नीचे खींचना चाहते हैं। शायद ऐसा करने से उन्हें बेहतर महसूस होता है।'

अभिनेता ने आलोचना को लेकर कहा, 'अगर वे वहां नहीं पहुंच पाते जहां आप पहुंचे हैं, तो उनके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वे इसके लिए मेहनत करें या आपकी आलोचना करें। आलोचना करना आमतौर पर आसान होता है। अब मैं इसे दिल पर नहीं लेता। मैं बस एक और पहाड़, एक और सीढ़ी, एक और चुनौती की तलाश में रहता हूं। आखिर, असली खुशी कभी भी सबसे ऊपर खड़े होने में नहीं थी। खुशी तो हमेशा ऊपर चढ़ने में रही है। है ना!

इस पोस्ट के साथ कई तस्वीरें भी साझा की है। इन तस्वीरों में अभिनेता खेर सीढ़ी पर बैठकर अलग-अलग पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह उनके उस संदेश को दिखाता है जिसमें वे लगातार कोशिश करने, आगे बढ़ने और नई चुनौतियों को अपनाने की खुशी की बात करते हैं।

इसके पहले अनुपम खेर ने 'आई एम एन इंडियन' नाम से एक दमदार और भावुक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में खेर ने भारतीयों से जुड़ी कई आम धारणाओं और रूढ़ियों पर बात की, चाहे वे देश में हों या विदेश में। प्रोफेशनल तौर पर बात करें तो अनुपम खेर आखिरी बार फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' में नजर आए थे, जिसे उन्होंने खुद डायरेक्ट भी किया था।

प्रियंका चोपड़ा ने की 'ऑब्सेशन' की तारीफ

हॉलीवुड में अवसरों की दीवारें टूट रही हैं

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस ने निर्माता बनने और अमेरिका में अपने करियर को आगे बढ़ाने की इच्छा पर खुलकर बात की। उन्होंने यह भी कहा कि अब हॉलीवुड में नए कलाकारों और फिल्म निर्माताओं के लिए प्रवेश की बाधाएं पहले की तुलना में काफी कम हो गई हैं। प्रियंका ने कम बजट की सफल हॉरर फिल्म ऑब्सेशन का उदाहरण देते हुए कहा कि आज के दौर में प्रतिभाशाली लोगों के लिए अवसरों के नए दरवाजे खुल रहे हैं। बुधवार को आयोजित कैंस लायंस सम्मेलन में शामिल हुईं प्रियंका ने कहा, 'मुझे लगता है कि अगर आपके पास कोई अच्छा विचार है तो आप उसे शूट कर सकते हैं, यूट्यूब पर डाल सकते हैं और वह 'ऑब्सेशन' जैसी फिल्म बन सकती है, जो हाल ही में रिलीज हुई है।'

उन्होंने आगे कहा, 'मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए यह बेहद शानदार समय है, क्योंकि आज के दौर में विचार ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी हैं।' प्रियंका ने बताया कि जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब हालात इतने आसान नहीं थे। पिछले एक दशक से हॉलीवुड में अपना करियर बना रहीं अभिनेत्री ने कहा कि शुरुआत में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनका फिल्मी दुनिया से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने कहा, 'मेरे माता-पिता डॉक्टर थे, इसलिए हममें से किसी को भी यह नहीं पता था कि फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़ना है। जब मैंने शुरुआत की थी, तब यह बहुत सीमित और खास लोगों तक पहुंच वाला क्षेत्र था। अगर आपको फिल्म निर्माण में आना होता था तो पहले यह तय करना पड़ता था कि आप किस विभाग में काम करना चाहते हैं।'

प्रियंका ने अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा कि उन्हें बताया गया था कि भारतीय सिनेमा कभी हॉलीवुड जितना वैश्विक नहीं बन पाएगा, क्योंकि भारतीय फिल्में अंग्रेजी भाषा में नहीं होतीं। उन्होंने कहा, 'मुझे बताया जाता था कि भारतीय सिनेमा कभी हॉलीवुड जितना वैश्विक नहीं होगा, क्योंकि हमारी फिल्में अंग्रेजी में नहीं बनतीं और हर कोई हिंदी, तेलुगु, मराठी या अन्य भारतीय भाषाओं को नहीं समझता।'

अभिनेत्री ने बताया कि उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस इसलिए शुरू किया ताकि नए फिल्मकारों और उन रचनात्मक लोगों को मंच मिल सके, जिनके पास बेहतरीन विचार तो हैं, लेकिन उद्योग के दरवाजे खोलने के लिए जरूरी संसाधन या संपर्क नहीं हैं। प्रियंका ने कहा, 'मैं ऐसे नए फिल्मकारों का समर्थन करना चाहती हूं जिनके पास शानदार विचार हैं, लेकिन उनके पास उन अवसरों तक पहुंच नहीं है, जिन तक मैं उन्हें पहुंचाने में मदद कर सकती हूं।' हाल ही में स्ट्रीमिंग हिट्स सिटाडेल और हेड्स ऑफ स्टेट का हिस्सा रहीं प्रियंका ने अपने अंग्रेजी भाषा के करियर को लेकर भी खुलकर बात की।

उन्होंने कहा, 'हिंदी सिनेमा में मैंने सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों और कलाकारों के साथ काम किया है। मैंने कई शानदार कहानियां और अलग-अलग शैलियों की फिल्में की हैं। लेकिन अमेरिका और हॉलीवुड में अपने अंग्रेजी भाषा के काम में मुझे अभी वैसी विविधता और अवसर उतने नहीं मिले हैं।'

प्रियंका का मानना है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और कोविड-19 महामारी के दौरान बदली दर्शकों की आदतों ने दुनिया भर की सामग्री को नए दर्शक दिए हैं। उनके अनुसार, अब लोग विभिन्न देशों और भाषाओं की कहानियों को पहले से कहीं ज्यादा अपनाने लगे हैं, जिससे वैश्विक मनोरंजन उद्योग में नई संभावनाएं पैदा हुई हैं।

कुब्रा सैत ने एडीएचडी के साथ अपने अनुभव पर की बात

अभिनेत्री कुब्रा सैत ने एक बार फिर मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोडायवर्सिटी पर अहम चर्चा छेड़ते हुए एडीएचडी (अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर) के साथ अपने अनुभव को बेहद ईमानदारी और सहज अंदाज़ में साझा किया है। अपने खास हास्य और बेबाकी के साथ उन्होंने बताया कि बचपन में उन्हें अक्सर 'ड्रामेबाज़' और 'बेपरवाह' कहा जाता था, क्योंकि उनका मन हमेशा कल्पनाओं की दुनिया में खोया रहता था। वीडियो में कुब्रा कहती हैं, 'बचपन में मुझे तीन बातें बार-बार सुनने को मिलती थीं, 'कुब्रा, तुम बहुत ड्रामेबाज़ हो', 'तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है', 'ज़रा ध्यान दो।' जब बाकी बच्चे मैथ्स की क्लास में सवाल हल कर रहे होते थे, तब मैं अपने दिमाग में मर्डर मिस्ट्री की कहानी बुन रही होती थी, फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतने पर स्पीच की रिहर्सल कर रही होती थी, अपने भविष्य के पति और मां के बीच बहस की कल्पना कर रही होती थी और लंच से पहले ही तीन आवारा बिल्लियों को बचा चुकी होती थी।'

वह आगे बताती हैं कि बड़े होने पर उन्हें पता चला कि उन्हें एडीएचडी है और तभी उन्हें ज़िंदगी की कई बातें समझ आने लगीं। वे कहती हैं, 'अधूरे रह जाने वाले प्रोजेक्ट्स, किसी एक काम में घंटों तक पूरी तरह डूब जाना, ब्राउज़र में 57 टैब खुले रखना, कमरे में क्यों आई थी यह भूल जाना, लेकिन 2009 में किसी ने क्या पहना था, किसने तारीफ की थी या किसने क्या कहा था, यह सब याद रहते थे।

मजेदार बात यह है कि यही दिमाग कभी अपनी चाबियां खो देता है, लेकिन नई दुनिया रच सकता है, कहानियां लिख सकता है, बिज़नेस शुरू कर सकता है, कॉमेडी लिख सकता है और कभी-कभी रात के दो बजे ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लेता है, क्योंकि उस समय वह चीज़ उसे आध्यात्मिक रूप से जरूरी लगती है।' एडीएचडी को चुनौती और ताकत दोनों बताते हुए कुब्रा कहती हैं, 'सच कहूँ तो यह थका देने वाला है, अराजक है, महंगा भी पड़ सकता है, लेकिन यह एक सुपरपावर भी है।' वीडियो के अंत में अपने चिर-परिचित मज़ाकिया अंदाज़ में वह कहती हैं, 'मैंने तो सिर्फ एक मैसेज का जवाब देने के लिए फोन उठाया था, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब यह पूरी रील बना डाली। लेकिन कंटेंट तो अच्छा बन गया!' अपनी इस ईमानदार और प्रेरणादायक बातचीत के ज़रिए कुब्रा सैत ने न्यूरोडायवर्सिटी के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश एक बार फिर दिया है। उन्होंने बताया कि एडीएचडी अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से समझा और अपनाया जाए, तो यही व्यक्ति की रचनात्मकता, कल्पनाशक्ति और दृढ़ता की सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है।

रीमेक्स ने फ्रेश कहानियों की जगह कम की

शाहिद कपूर ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल उनके पास सिर्फ दो बड़े प्रोजेक्ट्स 'कॉकटेल 2' और 'फर्जी सीजन 2' हैं। हाल ही में जब उनसे एक मीडिया इंट्रैक्शन में उनकी 9 आगामी फिल्मों की सूची के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा... 'अगर किसी को जानना है कि मैं आगे क्या कर रहा हूं, तो सीधे मुझे फोन कर लेना चाहिए। फिलहाल 'फर्जी 2' की करीब 60 प्रतिशत शूटिंग पूरी हो चुकी है और सितंबर तक इसका काम खत्म होने की उम्मीद है। बातचीत में शाहिद ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मौजूदा स्थिति पर भी खुलकर राय रखी।

उन्होंने माना कि हिंदी सिनेमा फिलहाल चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। लगातार रीमेक और फ्रेंचाइज फिल्मों पर ज्यादा जोर देने से नए राइटर्स और नई कहानियों के लिए जगह कम हो गई है।

बहन अंशुला की शादी को लेकर उत्साहित हैं अर्जुन कपूर

बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर अपनी छोटी बहन अंशुला कपूर की शादी को लेकर काफी उत्साहित हैं। अंशुला जल्द ही अपने मंगेतर रोहन ठक्कर के साथ विवाह बंधन में बंधने वाली हैं और कपूर परिवार में शादी की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं। अर्जुन कपूर ने मंगलवार को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर सगाई समारोह की कुछ तस्वीरें और वीडियो साझा किए। इसके साथ उन्होंने अपनी बहन के लिए एक भावुक संदेश भी लिखा। अर्जुन ने लिखा, 'अंश, अभी तो बस शुरुआत हुई है। एक शाम ही बीती है और मुझे पहले से ही लग रहा है कि यह समय बहुत तेजी से निकल जाएगा। तुम दोनों के लिए मैं बेहद खुश और उत्साहित हूं। अब शादी के जश्न का इंतजार नहीं हो रहा है।' फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर की शादी से जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत हाल ही में 'माता की चौकी' के आयोजन के साथ हुई। इस मौके पर अंशुला की चाची और अभिनेता संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो साझा किए। महीप कपूर ने पोस्ट के साथ लिखा, 'शादी की शुरुआत... जय माता दी।'

वेदांग रैना की नई फिल्म में नाओमिका सरन के साथ प्रगति श्रीवास्तव भी निभाएंगी अहम रोल

बॉलीवुड में इन दिनों नई जोड़ियों और नई कहानियों को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच अभिनेता वेदांग रैना की आने वाली फिल्म को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। अब तक चर्चा थी कि इस फिल्म में वेदांग के साथ नाओमिका सरन नजर आएंगी, लेकिन अब खबर है कि फिल्म में एक और अभिनेत्री प्रगति श्रीवास्तव की भी एंट्री हो गई है। बताया जा रहा है कि यह फिल्म रोमांस, कॉमेडी और रहस्य से भरपूर होगी और इसकी कहानी में दोनों अभिनेत्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जानकारी के मुताबिक, फिल्म का नाम अभी तय नहीं किया गया है। फिल्म का निर्माण मैडॉक फिल्म्स कर रहा है। वहीं निर्देशन की जिम्मेदारी जगदीप सिद्धू पर हैं। फिल्म की कहानी को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इसमें एक दिलचस्प प्रेम कहानी देखने को मिलेगी, जिसमें कई रोमांचक मोड़ होंगे। फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, प्रगति श्रीवास्तव का किरदार फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बताया जा रहा है कि फिल्म में वेदांग रैना के किरदार की जिंदगी में दो अलग-अलग प्रेम संबंध देखने को मिलेंगे। एक ओर नाओमिका सरन का किरदार होगा और दूसरी ओर प्रगति श्रीवास्तव का। ऐसे में फिल्म की कहानी को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ रही है।

सूत्र ने बताया कि फिल्म की ज्यादातर शूटिंग पूरी हो चुकी है। केवल कुछ दिनों का काम बाकी है। इसके बाद निर्माण कार्य और अन्य तैयारियां पूरी की जाएंगी। माना जा रहा है कि फिल्म को साल 2026 के आखिर तक सिनेमाघरों में रिलीज किया जा सकता है। प्रगति श्रीवास्तव की बात करें तो इससे पहले उन्होंने साउथ फिल्मों में काम किया है और धीरे-धीरे हिंदी फिल्म जगत में भी अपनी पहचान बना रही हैं। वह पहले प्रकाश झा की 'जनादेश' और आनंद एल राय की 'नखरेवाली' में काम कर चुकी हैं। अब इस नई फिल्म के जरिए वह बड़े स्तर पर दर्शकों के सामने आएंगी।

दूसरी ओर, नाओमिका सरन भी लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। वह हिंदी फिल्म जगत के बेहद चर्चित परिवार से ताल्लुक रखती हैं। नाओमिका, हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार माने जाने वाले राजेश खन्ना और मशहूर अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की नातिन हैं। उनकी मां रिंकी खन्ना भी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। ऐसे में नाओमिका की फिल्मी शुरुआत को लेकर पहले से ही काफी चर्चा बनी हुई है। वहीं वेदांग रैना भी अपने करियर के महत्वपूर्ण दौर में हैं। उनकी एक और बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मैं वारस आऊंगा' जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में उनके साथ शरवरी वाघ, नसीरुद्दीन शाह और दिलजीत दोसांझ जैसे बड़े कलाकार नजर आएंगे।

विकसित भारत संकल्प यात्रा : मोहला में पदयात्रा निकालकर दिया स्वच्छता और नशा मुक्ति का संदेश

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी अंतर्गत जिला मुख्यालय मोहला में गत दिवस विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनजागरूकता पदयात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों को स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ भारती चंद्राकर, डिप्टी कलेक्टर डीआर ध्रुव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कमर्चारी, जनप्रतिनिधि, स्कूली छात्र-छात्राएं, स्व-सहायता समूह की महिलाएं तथा बड़ी संख्या में नगरवासी शामिल हुए।

पदयात्रा का शुभारंभ जनपद पंचायत मोहला परिसर से किया गया। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मां छूरिया मंदिर प्रांगण तक पहुंची। पूरे मार्ग में प्रतिभागियों ने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जनकल्याण से जुड़े संदेशों वाले नारे एवं बैनर लेकर लोगों को जागरूक किया। स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक रैली में भाग लेते हुए स्वच्छता एवं स्वस्थ जीवनशैली को अपनाने का संदेश दिया। वहीं महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्यों ने भी जनजागरूकता अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

रैली के दौरान नागरिकों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के संबंध में जानकारी दी गई। लोगों को घरों एवं सार्वजनिक स्थलों पर कचरे का उचित प्रबंधन करने, गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग रखने तथा स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि स्वच्छता केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और जनसहभागिता से ही स्वच्छ एवं विकसित समाज का निर्माण संभव है।

मां छूरिया मंदिर प्रांगण में आयोजित समापन कार्यक्रम में स्वच्छता एवं नशा मुक्ति विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) भारती चंद्राकर ने उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता बनाए रखने, पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने तथा नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता आवश्यक है और स्वच्छता एवं नशा मुक्त समाज इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने घर, मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने में सक्रिय योगदान दें तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन करें। साथ ही युवाओं और समाज के सभी वर्गों से नशा मुक्त जीवन अपनाने का आह्वान किया गया। जनजागरूकता पदयात्रा के माध्यम से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जनकल्याण और नशा मुक्ति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लोगों को जागरूक करने का सफल प्रयास किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों की सहभागिता ने यह संदेश दिया कि समाज के सामूहिक प्रयासों से ही स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित भारत के संकल्प को साकार किया जा सकता है।

खास खबर

देश की लोकतंत्र का काला अध्याय रहा है कांग्रेस की इमरजेंसी : राजेश गुप्ता

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

प्रदेशः भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के सह- कार्यालय प्रभारी राजेश गुप्ता अग्रहरि ने देश के लोक तंत्र पर कांग्रेस की इमरजेंसी को काला दाग बताते हुए कहा कि सिर्फ एक संसदीय क्षेत्र रायबरेली चुनाव को हाई कोर्ट द्वारा रद्द कर दिए जाने से सन 1975 में कांग्रेस द्वारा देश में आपातकाल लगा दिया गया। इमरजेंसी का विरोध करने वाले सम्माननीयो को तथा देश के बड़े बड़े नेताओं को ? जेल ? मे ठूंस दिया गया।

देश के जुझारू नेता राजनारायण जी को रायबरेली से फर्जी चुनाव करा कर हरा देने वाली तत्कालीन प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने कोर्ट के आदेश को नही माना और हार के डर से देश में आपातकाल थोप दिया, सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र के लिए इंदिरा गांधी ने पूरु देश को आपातकाल की भट्ठी में झोंक दिया, इंदिरा गांधी के इस तानाशाही की लगभग सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया, आंदोलन किए जाने पर सभी बड़े नेताओं को मीसा कानून के तहत जेल में धकेल दिए गए। सर्वमान्य नेता अटल बिहारी वाजपेई, लालकृष्ण आडवाणी, सर्वोदयी नेता जय प्रकाश नारायण, राज नारायण, चौधरी चरणसिंह आदि बड़े -बड़े नेताओं को जेल भेज दिया गया, समाचार पत्रो पर सेंसर शीप लगाकर जनता की अभिव्यक्ति का गला घोंट दीया गया, ऐसे तानाशाही से राज चलाने वाले, जनता की आवाज का गला घोंटने वाली कांग्रेस पार्टी को उसके करनी के कारण देश की जनता हर चुनाव में नकार रही है, जगह-जगह उन्हें हार का मुख देखना पड़ रहा है।

युवा नेता अग्रहरि ने कहा कि अब वो तानाशाही, अधिनायक वाद का जमाना नहीं रहा, देश को प्रगति पथ के उच्च सोपान में ले जाने वाले राष्ट्र नायक व करिश्माई नेतृत्व वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमाना है। जिससे देश की जनता हर मायनो में खुश है और उनके सहयोगी राजग गठबंधन को हर बार जीता कर देश की बागडोर संभालने का हुक्म दे रही है। वहीं देश में आपातकाल जैसे काला कानून व संविधान का गला घोंटने वाली कांग्रेस पार्टी को ठीक तरह से विपक्षी बनने का भी मौका नहीं दे रही है। श्री अग्रहरि ने यह भी कहा कि कांग्रेस के लिए यह अधोपतन का दिन है।

निगम का कर्मचारी बनाकर मकान बनाने के नाम पर 8 लाख से अधिक की ठगी

राजनांदगांव। बसंतपुर थाना पुलिस ने बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर निगम का कमर्चारी बनाकर अटल आवास और हाउसिंग बोर्ड में मकान दिलाने के नाम पर 8 लाख 17 हजार रुपए की ठगी करने के मामले में एक साथी आरोपी को गिरफ्तार किया हैं, आरोपी द्वारा स्वयं को नगर निगम का कमर्चारी बाबू बात कर लोगों को झांसा देकर धोखाधड़ी किया गया था, शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया हैं। पूरे मामले में प्रार्थियों के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें नगर निगम का कमर्चारी बनाकर अटल आवास और हाउसिंग बोर्ड में मकान दिलाने के नाम पर आरोपी योगेश्वर पांडे के द्वारा ठगी की घटना को अंजाम दिया गया और अलग-अलग तारीखों पर प्राथिर्यों से 8 लाख 17 हजार रुपए आरोपी के द्वारा ठगे गए, आरोपी स्वयं को नगर निगम राजनांदगांव का कर्मचारी बाबू बताता था और धोखाधड़ी की घटना कौन जान देता था, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से अच्छी पहचान होने का झूठा दावा करते हुए प्राथिर्यों से पैसे हड़पने का काम आरोपी के द्वारा किया जाता था, इसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी योगेश्वर पांडे को गिरफ्तार कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया हैं।

भोरमदेव जंगल सफारी बनी छग के इको-टूरिज्म की नई पहचान

पर्यटन, प्रकृति और रोजगार का नया आयाम, एक माह में ही पहुंचे 480 से ज्यादा पर्यटक

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

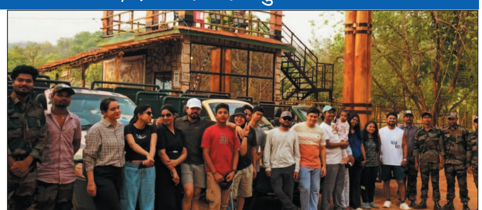

छत्तीसगढ़ सरकार की इको-टूरिज्म पहल के तहत विकसित भोरमदेव जंगल सफारी संचालन के पहले ही महीने में छत्तीसगढ़ के इको-टूरिज्म की नई पहचान बनकर उभरी है। जंगल सफारी प्रकृति प्रेमियों और रोमांच के शौकीनों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गई है, सिर्फ एक माह में ही 489 से अधिक पर्यटक यहां पहुंचे है, वहीं स्थानीय युवाओं, वन प्रबंधन समिति और स्व-सहायता समूहों को रोजगार एवं आमदनी के नए अवसर मिले हैं। प्रकृति, रोमांच और स्थानीय विकास का सफल संगम बनी यह पहल भोरमदेव को राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में स्थापित करने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा तथा वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में शुरू की गई यह जंगल सफारी आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गई है। वन मंडलाधिकारी निखिल अग्रवाल ने बताया कि भोरमदेव जंगल सफारी का उद्घाटन 3 मई 2026 को किया गया तथा 4 मई 2026 से पर्यटकों के लिए इसका संचालन शुरू हुआ। मानसून को देखते हुए 4 जून 2026 से सफारी को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। मात्र एक माह के संचालन के दौरान 480 से अधिक पर्यटकों ने जंगल सफारी का आनंद लिया, जिससे पौने 3 लाख रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। बारिश के बाद नवंबर माह से इसका संचालन फिर से शुरू होगा।

पर्यटन के साथ स्थानीय लोगों को मिला रोजगार

भोरमदेव जंगल सफारी की शुरुआत से स्थानीय लोगों को रोजगार और आय के नए अवसर मिले हैं। केवल एक महीने के संचालन में वाहन चालक, गाइड और गेट कीपर के रूप में कार्यरत 17 स्थानीय युवाओं ने 75 हजार रुपये से अधिक की आय अर्जित की। वहीं वन प्रबंधन समिति को 92 हजार और वन विभाग को 26 हजार रुपये से अधिक की आय प्राप्त हुई। सफारी परिसर में स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित कैंटीन भी पर्यटकों की पसंद बनी रही। एक माह में कैंटीन से 20 हजार रुपये से अधिक का मुनाफा हुआ, जिससे समूह की महिलाओं की आय बढ़ी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूती मिली।

वन्यजीवों की रोमांचक साइटिंग ने बढ़ाया आकर्षण

करीब 36 किलोमीटर लंबी जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को कई वन्यजीवों और पक्षियों को करीब से देखने का अवसर मिला। सफारी में भारतीय गौर, भालू, नीलगाय, सांभर, कोटरी (बार्किंग डियर), बाघ के पदचिह्न (टाइगर पगमार्क), जंगली मुर्गा, विभिन्न प्रजातियों के पक्षी और रंग-बिरंगी तितलियां पर्यटकों के लिए खास आकर्षण रहीं। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर वातावरण ने सफारी को रोमांचक और यादगार अनुभव बना दिया।

सिर्फ सफारी ही नहीं, उद्यान भी बना आकर्षण का केंद्र

जंगल सफारी के साथ-साथ भोरमदेव का प्राकृतिक उद्यान भी पर्यटकों की पसंद बन रहा है। सफारी का आनंद लेने वाले पर्यटकों के अलावा 1500 से अधिक लोगों ने उद्यान का भी भ्रमण किया। इससे साफ है कि भोरमदेव क्षेत्र धीरे-धीरे प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपनी अलग पहचान बना रहा है।

इको-टूरिज्म की नई पहचान

वन मंडलाधिकारी श्री निखिल अग्रवाल ने बताया कि लगभग 352 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले भोरमदेव अभयारण्य में 36 किलोमीटर लंबा जंगल सफारी मार्ग तैयार किया गया है। सफारी का मुख्य प्रवेश द्वार भोरमदेव मंदिर के पास करियाआमा क्षेत्र में स्थित है, जहां से पर्यटक अपनी जंगल यात्रा शुरू करते हैं। इस सफारी के माध्यम से पर्यटकों को छत्तीसगढ़ के समृद्ध वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने का अवसर मिल रहा है। साथ ही, इससे स्थानीय लोगों को रोजगार और आय के नए अवसर भी मिल रहे हैं।

राजनांदगांव शहर के ठाकुर प्यारेलाल स्कूल परिसर के पास अतिक्रमण हटाने पहुंची निगम की टीम

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

राजनांदगांव शहर के ठाकुर प्यारेलाल स्कूल परिसर के सामने अतिक्रमण को हटाने नगर निगम की टीम पहुंची थी जहां नगर निगम की टीम को बैरंग लौटना पड़ा दूकानदार और कांग्रेस के विरोध के कारण निगम की टीम जेसीबी लेकर उल्टे पांव लौट गई, निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी कुछ दुकान अतिक्रमण करके बनाया गया है और वहां शासकीय राशन दुकान खोलना हैं, जिस पर कार्रवाई के लिए टीम पहुंची थी।

ठाकुर प्यारेलाल स्कूल परिसर के सामने कई अवैध दुकानों का निर्माण किया गया है जिसे हटाने नगर निगम की जेसीबी टीम वहां पहुंची थी और नगर निगम के द्वारा वहां शासकीय राशन दुकान खोला जाएगा जिस पर कार्रवाई करने टीम पहुंची थी, दुकानदार और कांग्रेस के विरोध के कारण उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा कांग्रेस का कहना है कि अपना जीवन यापन कर रहे हैं यह दुकानदार ठेला गुमटी लगाकर और गरीबों के ऊपर ही निगम की कार्रवाई होती है बड़े लोगों पर निगम की कार्वाई नहीं होती इसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ और निगम की टीम वापस हो गई।

राजनांदगांव में जिला स्तरीय पल्स पोलियो अभियान आज से, जागरूकता रथ को किया रवाना

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

जिला स्तरीय पल्स पोलियो अभियान के संबंध में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजनांदगांव में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान पल्स पोलियो अभियान के जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

कार्यशाला में बताया गया कि जिला स्तरीय पल्स पोलियो अभियान के प्रथम दिवस 28, 29 एवं 30 जून 2026 को जिले के 0-5 वर्ष तक के कुल 111770 बच्चों को पोलियो की दो बूंद दवा पिलायी जाएगी। अभियान के प्रथम दिवस 28 जून को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बूथ के माध्यम से पल्स पोलियो की खुराक बच्चों को पिलायी जायेगी तथा 29 एवं 30 जून को स्वास्थ्य कार्यकत्ताओं द्वारा घर-घर भ्रमण कर बच्चों को शत-प्रतिशत दवा पिलायी जाएगी। पोलियो की दवा पिलाने के लिए जिले में कुल 447 बूथ बनाए गए है। 89 सुपरवाईजर की ड्यूटी लगाई गई है। कुल 894 टीम का गठन किया गया है। 1788 बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। अभियान को सफल बनाने के लिए मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्ताओं तथा अन्य समाजिक संस्थाओं का विशेष योगदान हेतु समन्वयक किया गया है। पोलियो की दवा पिलाने से कोई भी बच्चा न छूटे इसके लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ईंट भों, मदरसों और छात्रावासों के लिए ट्रांजिट और मोबाइल टीमें भी गठित की गई हैं।

शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में माईकिंग एवं दीवाल लेखन के माध्यम से पल्स पोलियो अभियान से नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही जिला स्तरीय मॉनिटरिंग टीम एवं कंट्रोल रूम की स्थापना कर ली गयी है। जिसका मोबाइल नंबर 7744356770 है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 0-5 वर्ष के सभी बच्चों के अभिभावकों से बूथ में पहुंचकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने की अपील की गई है। कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. बीएल तुलावी, सर्विलेंस मेंडिकल ऑफिसर डब्लूएचओ डॉ. असिम रियाज खान, खंड चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक विकास राठौर, जिला डाटा प्रबंधक एनएचएम अखिलेश चोपड़ा, शहरी कार्यक्रम प्रबंधक पूजा मेश्राम, जिला सलाहकर आरएमएनसीएचए स्नेहा जैन, अखिलेश नारायण सिंह एवं विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक, विकासखंड डाटा प्रबंधक, बीईटीओ एवं समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी उपस्थित थे।

शहर के पास सनसिटी कॉलोनी में 20 किलो चांदी के बर्तन सहित अन्य सामान की चोरी, जांच में जुटी पुलिस

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

शहर के पॉश सनसिटी कॉलोनी में बड़ी चोरी की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया, नकाबपोश चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए करीब 15 से 20 किलो चांदी के बर्तन और अन्य कीमती जेवरात पर हाथ साफ कर दिया, घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की हैं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी, आरोपियों द्वारा रात के समय घटना को अंजाम दिया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के चोर देर रात करीब 3 से 4 बजे के बीच मकान में पीछे की ओर से पहुंचे, उन्होंने खिड़की की ग्रिल तोड़कर घर में प्रवेश किया और ग्राउंड फ्लोर में रखी एक अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे चांदी के बर्तन, जेवरात और अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए, वारदात के समय घर के लोग दूसरे हिस्से में मौजूद थे, जिससे उन्हें चोरी की भनक नहीं लग सकी, सुबह जब परिवार के सदस्यों ने अलमारी खुली देखी तो चोरी का पता चला, इसके बाद तत्काल कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की।

एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि रात करीब 3 से 4 बजे के बीच सनसिटी कॉलोनी स्थित मकान में चोरी की वारदात हुई हैं, चोरों ने खिड़की की ग्रिल तोड़कर घर में प्रवेश किया और लगभग 15 से 20 किलो चांदी के बर्तन सहित अन्य सामान चोरी कर लिया, मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएसपी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर जांच की जा रही हैं, पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके, साथ ही तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं, पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

मॉडिफाइड साइलेंसरों पर कबीरधाम पुलिस ने की सख्त कार्रवाई, 10 जब्त साइलेंसर को किया नष्ट

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (आईपीएस) के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह एवं अमित पटेल के मार्गदर्शन में कबीरधाम पुलिस द्वारा बुलेट एवं अन्य वाहनों में लगाए जा रहे मॉडिफाइड साइलेंसरों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित करना तथा आम नागरिकों को अनावश्यक शोर से होने वाली परेशानी से राहत दिलाना है। इसी क्रम में कवर्धा एसडीओपी आशीष शुक्ला, थाना प्रभारी कोतवाली योगेश कश्यप एवं कोतवाली पुलिस टीम द्वारा कवर्धा शहर में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 10 वाहनों में नियमों के विपरीत मॉडिफाइड साइलेंसर लगे पाए गए। पुलिस टीम द्वारा संबंधित वाहनों को थाना कोतवाली लाया गया तथा वाहन मालिकों की उपस्थिति में मॉडिफाइड साइलेंसरों को निकलवाया गया। वाहन चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई तथा भविष्य में ऐसे साइलेंसरों का उपयोग नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई।

अभियान के दौरान जब्त किए गए 10 मॉडिफाइड साइलेंसर को थाना परिसर में एकत्रित किया गया। इसके बाद इन साइलेंसर को जेसीबी मशीन के माध्यम से नष्ट किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों को बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसरों से निकलने वाली अत्यधिक तेज आवाज आमजन, बुजुर्गों, मरीजों एवं विद्यार्थियों के लिए परेशानी का कारण बनती है तथा यह ध्वनि प्रदूषण के साथ-साथ यातायात नियमों का भी उल्लंघन है।

कवर्धा एसडीओपी आशीष शुक्ला ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कबीरधाम पुलिस जिले में लगातार अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की पहचान कर रही है और उनके विरुद्ध कोतवाली एवं यातायात पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने वाहनों में कंपनी द्वारा निर्धारित मानक उपकरणों का ही उपयोग करें तथा यातायात नियमों का पालन करें। कबीरधाम पुलिस ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यदि कहीं मॉडिफाइड साइलेंसर लगे वाहनों का संचालन होता दिखाई दे तो इसकी सूचना पुलिस को दें, ताकि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

मोहर्रम : मौलाना हाशिम कानपुरी ने दिया कर्बला से इंसाफ और भाईचारे का पैगाम

मस्जिदों और घरों में पढ़ी गई दुआएं आशूरा, रक्तदान, लंगर और सबील सहित किए सेवाकार्य

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

करबला के शहीदों की याद में शहर में यौमे आशूरा शुक्रवार को परम्परागत ढंग से मनाया गया। मस्जिदों और घरों में जहां लोगों ने दोपहर में खास तौर पर दुआए आशूरा पढ़ी, वहीं ताजियादारी,सवारी और अखाड़ा मुख्य जुलूस की रौनक रहे। जगह-जगह लंगर और सबील के जरिए खिदमते खल्क (मानव सेवा) का पैगाम दिया गया। वहीं विभिन्न कमेटियों की ओर से रक्तदान की भी पहल की गई।

यौमे आशूरा का जुलूस दोपहर बाद पावर हाउस ओवर ब्रिज पर इकट्ठा होना शुरू हुआ। इस दौरान जम कर बारिश होने लगी। लोग बारिश में भीगते हुए करबला के शहीदों की याद में या हुसैन की सदा बुलंद करते रहे। इस दौरान अखाड़े में हैरतअंगेज करतब दिखाते नौजवान आगे बढ़ते रहे। यहां से जुलूस सेक्टर-1 से सेंट्रल एवेन्यू और सेक्टर-5 चौक होते हुए रात में सेक्टर-6 मस्जिद तक पहुंचा। इसके बाद देर रात जुलूस करबला मैदान जीई रोड पहुंचा, जहां फातिहा ख्वानी के बाद लोग सुबह तक घर लौटे। मुहर्रम के 10 वें दिन यौमे आशूरा पर शहर की सभी मस्जिदों में दोपहर के वक्त नमाजे जुहर के बाद मिल कर दुआए आशूरा पढ़ी गई। वहीं मस्जिदों, इमामबाड़ों और ताजिया निकलने के रास्ते में जगह-जगह लंगर और सबील का इंतजाम किया गया था।

छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट की ओर से इमाम हुसैन की याद में रक्तदान शिविर और आम लंगर का आयोजन जामा मस्जिद सेक्टर-6 भिलाई में किया गया। जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने भागीदारी दी। इधर करबला कमेटी की ओर से भी करबला मैदान में राहगीरों के लिए शरबत की सबील का इंतजाम किया गया। वहीं कमेटी ने जुलूस की व्यवस्था देख रहे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर, डीएसपी चंद्रप्रकाश तिवारी और अन्य पुलिस अफसरों का इस्तकबाल किया।

इसके पहले ताजिए का जुलूस शहर की परंपरा अनुसार 25-26 जून की दरमियानी रात पावर हाउस चौक पर इकट्ठा हुआ। कैम्प, खुर्सीपार, फरीद नगर, सुपेला और सेक्टर क्षेत्र के तमाम ताजिया, अखाड़ा और सवारी की कमेटियां जुलूस के तौर पर पावर हाउस पहुंचे। जहां अखाड़े के करतब नौजवानों ने दिखाए। वहीं फातिहा ख्वानी हुई और सुबह-सुबह सभी कमेटियां वापस अपने अपने इमामबाड़े पहुंची। जहां से शुक्रवार दोपहर बाद मुख्य जुलूस के लिए सभी रवाना हुए और देर रात करबला मैदान पहुंचे।

तमाम ताजिया, अखाड़ा, सवारी कमेटी, करबला कमेटी, अंजुमन शहीदीया हाउसिंग बोर्ड के संस्थापक हाजी एमएच सिद्दीकी और अंजुमन हुसैनिया-इलाहाबादी पंचायती ताजिया के सदर हुसैन अली अशरफी ने मुहर्रम का जुलूस बिना किसी बाधा के संपन्न होने और कानून-व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम के सहयोग के और आम जनता का आभार जताया है।

भिलाई में नशीली टेबलेट बेचने वाला गिरफ्तार

दुर्ग। अवैध नशीली टेबलेट की बिक्री करने वाले आरोपी को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भिलाई के स्टेशन मरोदा क्षेत्र में आरोपी युवक अपने घर के सामने ही नशीली टेबलेट बेचने का धंधा लंबे समय से कर रहा था, लेकिन इस बार पुलिस ने आरोपी को 16.12 ग्राम टेबलेट के साथ दबोच लिया। दरअसल नेवई पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि स्टेशन मरोदा निवासी एक व्यक्ति अपने घर के सामने शिवपारा शीतला तालाब के पास अवैध रूप से नशीली टेबलेट बिक्री के लिए रखा हुआ है। इसके बाद फौरन पुलिस ने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर रेड कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान स्टेशन मरोदा शीतला पारा निवासी आरोपी सुजल सिंह, उम्र 22 वर्ष के कब्जे से ALPRAZOLAM TABLET I.P. 0.5 mg (ALPRAWIN 0.5) की 13 पत्तियां, कुल वजन 16.12 ग्राम एवं अनुमानित कीमत 52,000 की नशीली टेबलेट जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे केंद्रीय जेल दुर्ग भेजा गया।

जनदर्शन में मंत्री यादव ने सुनी जनता की समस्याएं

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग के गंजपारा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में कैबिनेट मंत्री एवं दुर्ग शहर विधायक गजेन्द्र यादव ने शुक्रवार को गंजपारा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में जनदर्शन में नागरिकों एवं कार्यकर्ताओं से सौजन्य भेंट कर उनकी समस्याओं, मांगों एवं सुझावों को गंभीरतापूर्वक सुने। जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए।

केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि शासन की प्राथमिकता आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य से नियमित जनदर्शन के माध्यम से लोगों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के साथ-साथ नागरिकों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान करना भी जनप्रतिनिधि की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसी भावना के अनुरूप वे नियमित रूप से जनदर्शन आयोजित कर लोगों से सीधे संवाद करते हैं और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक पहल करते हैं। जनदर्शन के दौरान मठपारा निवासी कक्षा चौथी की छात्रा प्रतिज्ञा सारथी से भी उनकी मुलाकात हुई। छात्रा की शिक्षा के प्रति लगन और उत्साह से प्रभावित होकर मंत्री श्री यादव ने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए सहयोग प्रदान किये तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली और मेहनती बच्चों की शिक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी तथा ऐसे विद्यार्थियों को हरसंभव प्रोत्साहन और सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100